

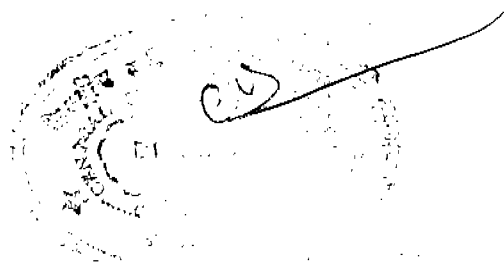


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 37] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 1, 1994/फाल्गुन 10, 1915

No. 37] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 1, 1994/PHALGUNA 10, 1915

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बजट अनुभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1994

फा. सं. 15 (38)-बी (डी)/93 :—निम्नलिखित को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

बजट 1994-95 वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह का भाषण
28 फरवरी, 1994

भाग 'क'

महोदय,

अत्यन्त सौभाग्य और विनम्रता की भावना से मैं वर्ष 1994-95 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

2. तीन वर्ष से कम समय गुजरा है, जब हमारी पार्टी ने उस समय एक प्रत्यक्ष सरकार के रूप में प्रधानमंत्री, श्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सत्ता संभाली, जिसके सापने एक

छिन्न-भिन्न अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का विशाल दायित्व था। प्रधानमंत्री ने वचन दिया था कि हम गंभीर आर्थिक संकट से निबटने और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ सतत विकास के मार्ग पर वापस लाने को उच्च प्राथमिकता देंगे। इस आदेश के अनुसरण में हमने आर्थिक पुनर्निर्माण और सुधार के दूरगामी कार्यक्रम निर्धारित किये।

3. भारत जैसे जटिल देश में आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करने के लिए तीन वर्ष की अवधि पर्याप्त नहीं है, परन्तु स्थिति का जायजा लेने के लिए यह समय काफी है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आर्थिक स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ है। वैदेशिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है।

—हमारा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार, जो जून, 1991 में 1 बिलियन डालर से कुछ अधिक था। अब 13 बिलियन डालर के लगभग हो गया है। हमारा स्वर्ण, जिसे विदेशों में गिरवी रख दिया गया था, हमारे कब्जे में वापस आ गया है।

—निर्यातकर्ता विनिमय दर और व्यापार नीतियों में हमारे व्यापक सुधारों का बहुत धन्य प्रत्युत्तर दे रहे हैं।

—हमारे तिमाही में वर्ष 1993-94 के प्रथम 10 महीनों में डालर के रूप में 21 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में वर्ष 1991-92 की तदनु रूप अवधि में 3 प्रतिशत की गिरावट और वर्ष 1992-93 में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

—सभी भय के बावजूद कि उदारीकरण से आयातों में भारी वृद्धि हो जाएगी, अप्रैल-जनवरी, 1993-94 के दौरान हमारा आयात, डालर के रूप में वर्ष 1992-93 की समतुल्य अवधि के दौरान किए गए आयातों से एक प्रतिशत से भी कम था। 1993-94 के राजकोषीय वर्ष के लिए आयातों के वर्ष 1990-91 से भी कम होने की संभावना है।

—वर्ष 1993-94 के दौरान हमारे भुगतान संतुलन में चालू खाते का घाटा वर्ष 1990-91 के 3 प्रतिशत से भी अधिक और 1992-93 के 2 प्रतिशत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का आधा प्रतिशत से भी कम होगा।

—कई लोगों की आशंका के विपरीत, रुपए की विनिमय दर एकीकरण और व्यापार नियंत्रण हटाए जाने के बावजूद उल्लेखनीय रूप में स्थिर रही। पहले की तरह हवाला लेन-देनों के माध्यम की बजाय विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में कानूनी माध्यमों से आ रही है।

—भारत के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास पुनःस्थापित हुआ है। विदेशी प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेश, जो वर्ष 1991-92 में मात्र 150 मिलियन डालर था, उसके वर्ष 1993-94 में लगभग 3 बिलियन डालर हो जाने की संभावना है।

4. घरेलू अर्थव्यवस्था की प्रगति भी उत्साहवर्धक है। मुद्रास्फीति को अग्रस्त, 1991 में 17 प्रतिशत के शीर्ष से कम करके वर्तमान में उस स्तर का लगभग आधा कर दिया गया है। कृषि संबंधी निष्पादन भी काफी अच्छा रहा है। सार्वजनिक प्रणाली में खाद्य भंडार पहली [जनवरी, 1994 को 23 मिलियन टन था। यह सात वर्षों में उच्चतम स्तर है और फसल की विफलताओं की किसी भी संभावना के एवज में अमूल्य बीमा प्रदान करता है। औद्योगिक उत्पादन में भी सुधार हो रहा है, यद्यपि जैसी हमने आशा की थी उससे यह काफी धीमा है। समग्र आर्थिक वृद्धि लगातार दूसरे वर्ष लगभग 4 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह भय कि सुधार कार्यक्रमों से बेरोजगारी में काफी वृद्धि हो सकती है, निराधार सिद्ध हुआ है। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत और रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के अद्यतन आंकड़े नवम्बर 1992 की तुलना में नवम्बर, 1993 में 1.4 प्रतिशत की कमी दर्शाते हैं।

5. वर्ष 1993-94 में उद्योग की धीमी प्रगति चिन्ता का विषय है और यह मुख्यतः पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में मंदी के कारण है। अगर पूंजीगत वस्तुओं को छोड़ दिया जाता है तो शेष विनिर्माण क्षेत्र दूसरी तिमाही में 6 प्रतिशत की वृद्धि

से अच्छा निष्पादन दर्शाता है और वर्ष की शेष अवधि में और सुधार होने का अनुमान है। पूंजीगत वस्तु उद्योगों में मन्दी प्रारम्भिक तौर पर निवेश संबंधी क्रियाकलापों में अस्थायी तौर पर कमी होने के कारण है, क्योंकि फर्मों को नई स्थितियों के अनुसार अपनी निवेश संबंधी योजनाओं को समायोजित करना होता है। इस बात के संकेत हैं कि पुनर्निर्माण की यह प्रक्रिया काफी आगे है और कई कंपनियाँ अपनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अब बड़े कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। इसलिए, निवेश में एक नया मोड़ प्रारंभ हो रहा है।

6. वास्तविक जीवन में स्थिति कभी भी समग्र रूप से सुखमय नहीं होती और कुछ चेतावनी के संकेत मौजूद होते हैं, जिन पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। हमने मूल रूप से जितना लक्ष्य निर्धारित किया था चालू वर्ष में उस स्तर तक राजकोषीय घाटा स्थिर रहना संभव नहीं हुआ है। वर्ष 1993-94 में औद्योगिक सुधार की धीमी गति के कारण राजस्व में गिरावट आई और कई खर्च भी बजट अनुमानों से अधिक हो गए। साधारणतया 1993-94 में राजकोषीय घाटे में कमी प्रत्याशा के विपरीत कम क्षतिकारक रही, क्योंकि यह मुख्यतया पर्याप्त निष्क्रिय औद्योगिक क्षमता और निम्न निवेश स्तर पर विद्यमान थे। परंतु, ज्यों ही निवेश में पुनर्स्थान होना शुरू होता है, हम राजकोषीय क्षेत्र में कमी बनाए रखना सहन नहीं कर सकते। जब तक चालू वर्ष में देखी गई गिरावट को तेजी से बदला नहीं जाता, इस बात का गंभीर खतरा है कि हम ऐसी स्थिति में वापस जा सकते हैं, जहां अत्यधिक सरकारी घाटा मुद्रास्फीति में वृद्धि करता है, चालू खाते का असंतुलन बढ़ाता है और व्याज दरों में वृद्धि करता है, जो जीवन स्तर बढ़ाने और पर्याप्त संख्या में उत्पादक रोजगार सृजित करने के लिए आवश्यक हमारी तीव्र आर्थिक वृद्धि लाना असंभव बना देता है।

7. इस बजट को बनाते समय मैंने छः मुख्य कार्यों की ओर ध्यान दिया है :

—पहला, हमें अपनी कर प्रणाली के सुधार और आधुनिकीकरण की गति तेज करनी चाहिए, जिसे हमने दो वर्ष पूर्व आरंभ किया था।

—दूसरे, हमें चालू वर्ष में राजकोषीय घाटे की बढ़ोतरी (स्लिपेज) को सुधारना चाहिए।

—तीसरे, हमें वैदेशिक क्षेत्र, जहां हमारे सुदृढ़ कार्य-निष्पादन ने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ चरणबद्ध एकरूपता की हमारी नीति का समर्थन किया है, में प्राप्त सराहनीय क्षमता को बनाए रखना चाहिए।

—चौथे, बजट को एक सुदृढ़ औद्योगिक सुधार, विशेषकर निवेश और पूंजीगत वस्तु उत्पादन के लिए एक प्रमुख प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए।

—पाँचवाँ, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें अपनी विकास नीतियों और कार्यक्रमों को हमारी अधिकतम जनता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रभावित करने वाली गरीबी, बेरोजगारी तथा सामाजिक नुकसान वाली समस्याओं को अधिक प्रभावी रूप से अनुकूल बनाने के लिए पुनः अभिमुख बनाना चाहिए।

—छठे, हमने अपनी बैंकिंग प्रणाली का जो पुनरुद्धार किया है, उसे सुदृढ़ करने एवं उसकी प्रगति में और तेजी लानी है।

8. पिछले वर्ष हम एक एकीकृत बाजार निर्धारित विनियम दर प्रणाली की ओर अग्रसर हुए थे। इस प्रणाली ने अत्यंत सुचारू रूप से कार्य किया है। अब अगला कदम बढ़ाने और चालू लेखों में परिवर्तनीयता की दिशा में बढ़ने का समय आ गया है। चालू लेखों में परिवर्तनीयता सभी चालू व्यापार लेन-देनों के लिए विदेशी मुद्रा तक हमारी पहुँच को अत्यधिक उदार बनाने और यात्रा, शिक्षा तथा डाक्टरी खर्चों के लिए भी विदेशी मुद्रा को उदार बनाएगी। यह निश्चित रूप से ऐसे लेन-देनों के लिए अवैध चैनलों पर निर्भरता को समाप्त करेगी। इन उदार नीतियों के व्यौरों की घोषणा रिजर्व बैंक द्वारा अलग से की जा रही है। अपनी विदेशी भुगतान व्यवस्था के प्रगामी उदारीकरण के अनुरूप, हम विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की समीक्षा करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो नये विधान द्वारा इसे प्रतिस्थापित करने सहित आवश्यक परिवर्तन करेंगे।

9. विदेशी प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेश की हमारी नीतियों से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं और इनसे हमारी विदेशी उधार पर निर्भरता को कम करने में सहायता मिली है। अनुमोदित अधिकांश प्रत्यक्ष निवेश महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा क्षेत्रों के लिए है। पिछले वर्ष के भरे बजट भाषण में जैसी परिकल्पना की गई थी, सरकार इस समय कई मुख्य निवेशकर्ता देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश करारों पर बातचीत कर रही है।

10. हमारा विदेशी ऋण, जो चिंता का कारण है, अब बहुत घीभी गति से बढ़ रहा है। इसमें 1980 के दशक के उत्तरार्ध में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 6 बिलियन डालर की वृद्धि हुई। वर्ष 1990-91 में ऋण में 8 बिलियन डालर से अधिक की वृद्धि हुई। वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 में मात्र लगभग 3 बिलियन डालर की औसत वृद्धि हुई। वर्ष 1993-94 के पूर्वार्ध में, विदेशी ऋण में केवल 300 मिलियन डालर की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, ऋण में हुई हाल की वृद्धि हमारे विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में तीव्र वृद्धि से प्रति संतुलित हो गई है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहूँगा कि हम इस पहलू के प्रति सजग रहेंगे, ताकि विदेशी ऋण विवेकपूर्ण स्तरों के भीतर रहें। भारत के ऋण जाल में फँसने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वास्तव में हमारा पूर्व में व्यय किए गए उच्च लागत वाले कुछ ऋण को छोड़कर सरल भुगतान स्थिति का प्रत्युत्तर देने का प्रस्ताव है।

भारतीय कंपनियों को पहले के विदेशी ऋणों का पूर्व-भुगतान करने की मुक्त रूप से अनुमति दी जाएगी।

11. माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि हमारा कुछ विदेशी ऋण अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से लिया गया है। हमने अपनी संकट की घड़ी में कोष से संपर्क किया था। अब हमारी भुगतान की स्थिति काफी सुधर गई है और हमारा प्रारक्षित भंडार सुविधाजनक स्तर तक पुनर्निर्मित हो गया है। हम समय से कुछ पूर्व ही कोष को वापसी-अदायगी करने की स्थिति में हैं। वर्ष 1994-95 में कोष को 1.4 बिलियन डालर की मूल और व्याज की वापसी अदायगी की जानी है। भुगतान की नियमित समय-अनुसूची का पालन करने की बजाय, हमारा इरादा पूरी राशि को वर्ष के प्रारंभ में ही समय-पूर्व भुगतान करने का है। पूर्व-भुगतान करने का यह निर्णय किसी भी अर्थ में कोष, जिसने हमारी आवश्यकता के समय हमारी अत्यधिक सहायता की है, के साथ उत्कृष्ट संबंधों को कम नहीं करता है। अगर स्थितिबोध आवश्यक हुआ तो हम पुनः वित्तीय सहायता मांगने में नहीं हिचकिचाएंगे।

12. वर्तमान में निर्यातकर्ताओं और अन्य विदेशी मुद्रा उपार्जकों को विदेशी मुद्रा में निश्चित लेखों में विदेशी मुद्रा प्राप्ति 15 प्रतिशत तक रखने की अनुमति दी जाती है। अनुमत्य प्रतिधारण की प्रतिशतता को 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। विशेष प्रोत्साहन के रूप में, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों तथा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाइयों और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की इकाइयों को, अनुमत्य प्रतिधारण 50 प्रतिशत होगा। यह सुविधा निर्यातकर्ताओं को आयातों के लिए भुगतान करते समय रूपान्तरण लागत व्यय करने से संरक्षण प्रदान करने के लिए है। आवश्यक अधिसूचनाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग से जारी की जा रही है।

13. राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता की चर्चा करते हुए, मैंने लंबे समय से महसूस किया है कि सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के असीमित आश्रय, राजकोषीय ढुंडियों के निर्गम द्वारा धन सृजित करके अपने घाटे का वित्तपोषण नहीं करना चाहिये। इस प्रथा ने प्रभावी मौद्रिक नीति लागू करने की रिजर्व बैंक की क्षमता को भी क्षीण किया है। सुधारात्मक उपाय के रूप में, मैं राजकोषीय ढुंडियों तक सरकार की गम्यता को तीन वर्षों तक चरणबद्ध करने का प्रस्ताव करता हूँ। वर्ष 1994-95 में बजट घाटे को अनुमानित सकल घाटे के एक प्रतिशत के लगभग दो-तिहाई अथवा 6,000 करोड़ रुपये तक सीमित किया जा रहा है। सामान्यतया, पूरे वर्ष के लिये राजकोषीय ढुंडियों का निवल निर्गम इस राशि से नहीं बढ़ना चाहिये। रिजर्व बैंक से यह सहमति भी हुई है कि वर्ष में किसी भी समय राजकोषीय ढुंडियों का निवल निर्गम दस लगातार कार्य

विवसों के लिये 9,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा होता है तो तदर्थ राजकोषीय ढुंडियों के स्तर को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक स्वतः ही बाजार में राजकोषीय ढुंडियाँ बेचेगा। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो आने वाले समय में राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन में महत्वपूर्ण सुधार करने में योगदान देगा और रिजर्व बैंक को प्रभावी मौद्रिक प्रबंध के लिए अधिक अवसर प्रदान करेगा। अनुवर्ती वर्षों में, तदर्थ राजकोषीय ढुंडियों का आश्रय लेना प्रणामी तौर पर कम किया जायेगा और वर्ष 1997-98 तक सरकार अपने घाटे के वित्तपोषण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक का प्रत्यक्ष आश्रय लेना बंद कर देगी और उसे अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार से उधार लेकर करनी होगी।

14. उद्योग और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में निवेश पर ब्याज दरों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बार-बार मांग होती रही है कि ब्याज दरों को कम किया जाना चाहिये। पिछले वर्षों में बैंकों द्वारा प्रभारित ऋण देने की न्यूनतम दरों को पहले ही तीन प्रतिशत तक कम किया जा चुका है। वित्तीय संस्थाओं ने भी अपनी प्रभावी दरें कम कर दी हैं। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं अब ऋण देने की अपनी न्यूनतम दर ब्याज के अतिरिक्त 1 प्रतिशत और कम करके 14 प्रतिशत कर रही है। इसी के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों की तीन वर्षों और उससे अधिक के सावधिक ऋणों पर ऋण देने की न्यूनतम दर भी 15 प्रतिशत से कम करके 14 प्रतिशत की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक अलग से अधिसूचना जारी कर रहा है। ये परिवर्तन कल से लागू होंगे और अर्थ-व्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करेंगे।

15. सरकार ने समसामयिक आवश्यकताओं के अनुसार कम्पनी अधिनियम को कारगर बनाने के लिये इस अधिनियम में कुछ संशोधनों का पहले ही प्रस्ताव किया था। भारतीय कंपनियों को ऐसा परिवेश प्रदान करने के लिए जिसमें कि वे उच्च प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें, इन प्रस्तावों में संशोधन करने के लिए उद्योग से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर पुनः विचार किया है और संसद में एक नया विधेयक पेश करने का प्रस्ताव किया गया है जो कि इन चिन्ताओं के प्रति अनुकूल होगा।

16. हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी शक्ति और बोलत के प्रमुख निर्धारक बन गये हैं। भारत को अपने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकियों की उपलब्धियों पर गर्व है, लेकिन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय नवीकरण का एक कारगर साधन बनाने के

लिये काफी कुछ किये जाने की आवश्यकता है। उत्पादन प्रक्रियाओं के लिये देशीय प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग को तेज करने के वास्ते, मैं अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत इस समय एकत्र किये जा रहे आयातित प्रौद्योगिकियों के लिये रायल्टी के भुगतानों पर लगने वाले 5 प्रतिशत उपकर को प्रौद्योगिकी विकास और प्रयोग संबंधी एक नये कोष में जमा करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह कोष देशीय विकसित प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यिक प्रयोगों के चरण तक पहुंचाने के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पास रहेगा। इस संबंध में अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे। जब मैं कर प्रस्तावों की चर्चा करूँगा, तब मैं अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ और उपायों का प्रस्ताव करूँगा।

17. मैं सदन को आश्वासन देना चाहूँगा कि हमारी नीतियाँ एक गतिशील और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धी औद्योगिक क्षेत्र का संवर्धन करने की दिशा में अग्रसर हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे पास कुशल जनशक्ति और उद्यमशीलता का असीम भंडार होने के कारण, भारतीय उद्योग के पास विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने की क्षमता और इच्छा है। सरकार और उद्योग दूसरी औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत करने में सक्रिय सहयोगियों के रूप में कार्य करेंगे, जो कि दोनों ही अधिक कारगर और अधिक रोजगारोन्मुखी हैं। इस वर्ष के लिए मेरे राजस्व, प्रस्तावों, जिनकी मैं बाद में चर्चा करूँगा, मैं औद्योगिक निवेश और पूंजीगत माल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपायों का एक मजबूत पैकेज शामिल है। भविष्य के संदर्भ में, हमारी औद्योगिक फर्में पूरे विश्व में पहुंचे और दूर-दराज तक, सुदूर देशों में उनके नाम की घर-घर में चर्चा हो, ऐसा मेरा एक सपना है।

18. अब मैं कृषि से संबंधित कुछ मुद्दों की ओर आता हूँ। कृषि को संस्थागत ग्रामीण ऋण का पर्याप्त प्रवाह ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये महत्वपूर्ण है और आवश्यकता की तुलना में इस समय यह प्रवाह अत्यंत कम है। इसके पीछे कारणों में, बैंकों और सहकारिताओं द्वारा की जाने वाली मध्यवर्तियों की उच्च लागतें, संस्थागत ढाँचे में बुनियादी कमजोरियों और ऋण तथा ब्याज दर नीति पर अस्थिर प्रतिबंध शामिल हैं। मैं ग्रामीण ऋण में दीर्घावधि सुधार के लिये आधार स्थापित करने के वास्ते अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रस्ताव करता हूँ। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्रामीण ऋण के लिये शीर्ष अभिकरण है। मैं इसकी शेयर पूंजी को बढ़ाने के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहा हूँ। और भारतीय रिजर्व बैंक भी इतनी ही राशि का अंशदान करेगा। इससे

नाबांड की शेयर पूंजी लगभग तिगुनी हो जाएगी और ग्रामीण ऋण की प्रणाली को मजबूत बनाने में शक्तिशाली नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिये इसे सुसज्जित करेगा।

19. ग्रामीण ऋण में एक प्रमुख चिंता का विषय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कमजोर स्थिति है। 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से, पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष लगभग 150 बैंकों ने घाटा दिखाया है। अधिकांश ने अपनी इक्विटी तथा प्रारक्षित भंडार को पूरी तरह समाप्त कर दिया है तथा कुछ में जमा राशियों में भी हानि हो रही है। यह एक अस्थिर स्थिति है और यदि इन बैंकों को पुनः लाभ प्रदान करने वाला बनाना है तो दीर्घावधि संरचनात्मक उपाय आवश्यक है। रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए अपने उधार देने के अभियान में उन्हें अधिक नम्यता प्रदान करने के लिए कुछ उपायों की पहले ही घोषणा की है। मेरा 1994-95 के दौरान पूरे देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 50 की वॉलेस शीटों को परिभाजित करने तथा अतिरिक्त पूंजी लगाने सहित व्यापक पुनर्संरचना आरम्भ करने का प्रस्ताव है। संरचनात्मक तथा सम्पन्न प्रितीन सहायता का स्वरूप और तौल-तरीका वर्ष के दौरान तैयार किया जाएगा। इन 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अनुभव बाद के वर्षों में अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रति हमारे दृष्टिकोण मार्गदर्शन करेगा। इस कार्यक्रम की सफलता राज्य सरकारों तथा प्रवर्तक बैंकों से पूर्ण सहयोग पर निर्भर करेगी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शेयरधारक एवं कर्मचारी भी हैं। हमारा उद्देश्य फिलहाल कमजोर एवं रूग्ण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य तथा विकेन्द्रीकृत ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ माध्यम में परिवर्तित करना है।

20. इसके अतिरिक्त, हमें सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के उपायों का पता लगाना चाहिए, जिन्होंने ऋण सहायता के माध्यम से ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष 1992-93 के दौरान सहकारिताओं द्वारा 6,295 करोड़ रुपये के नये ऋण प्रदान करने की तुलना में उनके 1993-94 के दौरान 8,500 करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशा है। 1994-95 के दौरान, हमारी 9,600 करोड़ रुपये तक और वृद्धि करने की योजना है। इस मात्रात्मक वृद्धि के साथ-साथ संगठनात्मक तथा संरचनात्मक परिवर्तन भी होने चाहिए जो वित्तीय व्यवहार्यता को सुनिश्चित करते हैं। सरकार का सहकारिता संरचना को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय करने का प्रस्ताव है। "नाबांड" सहकारिता प्रणाली को नया रूप देने और उसकी व्यवहार्यता में सुधार लाने के वास्ते राज्य विशेष विकास कार्य योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए राज्य तथा जिला सहकारी बैंकों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ सहमति ज्ञापन निष्पन्न करेगा।

21. ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत करने के इन उपायों के साथ-साथ ग्रामीण विकास के लिए बजट प्रावधान में काफी वृद्धि करना भी शामिल है, जिस पर मैं अभी आ

रहा हूं। यह सुनिश्चित करना भी हमारा उद्देश्य होगा कि कृषि संबंधी हमारी नीतियों से कृषकों पर से सभी अनावश्यक दबाव संपात होंगे। खाद्यान्न और अन्य कृषि वस्तुओं की अंतर्देशीय आवाजाही पर से प्रतिबंध पूर्ण रूप से हटाए जाने चाहिए, ताकि हमारे किसान भाई एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के लाभों का उपयोग कर सकें। उन्हें निर्यात करने के लिए भी अधिकाधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे वे न केवल हमारे राष्ट्रीय निर्यात प्रयासों में अपना योगदान दे सकें, बल्कि लाभप्रद निर्यात अवसरों से भी लाभ उठा सकें।

22. माननीय सदस्य जानते ही हैं कि हमने बैंकिंग प्रणाली में मूलभूत पुनर्संरचना आरंभ की है, जिसका लक्ष्य इसके परिचालनों की पूर्ण वित्तीय व्यवहार्यता और इसकी प्रतिस्पर्धी क्षमता को मजबूत बनाने को सुनिश्चित करना है। मैं राष्ट्रीयकृत बैंकों को 1993-94 में पूंजी अंशदान के रूप में 5,700 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है, जिससे उन्हें डुबन्त और संदिग्ध ऋणों के लिए आवश्यक प्रावधान करने तथा नए पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड पूरा करने में सहायता मिल सके। पिछले वर्ष मैंने उल्लेख किया था कि 1994-95 और 1995-96 में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी और यह बोझ पूर्णतया बजट में वहन नहीं किया जा सकता था। सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि दिसम्बर, 1993 और जनवरी, 1994 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने इक्विटी के निर्गम द्वारा जनता से सफलतापूर्वक 2,200 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि एकत्र की और एक बांड निर्गम के माध्यम से और 1,000 करोड़ रुपये एकत्र किए। राष्ट्रीयकृत बैंकों को इसी प्रकार पूंजी बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति देने और बजट पर बोझ को कम करने के लिए लोकसभा में शीतकालीन सत्र में विधायी संशोधन पेश किए गए। उन्हें शीघ्रता से पारित किए जाने से इनमें से कई बैंकों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित पूंजी जुटाने में सहायता मिलेगी। फिर भी, कई राष्ट्रीयकृत बैंकों को वर्ष 1994-95 के दौरान अतिरिक्त सहायता की अपेक्षा होगी और मैं इन बैंकों के लिए अतिरिक्त पूंजी अंशदान के रूप में वर्ष 1994-95 में 5,600 करोड़ रुपये प्रदान कर रहा हूं। पहले की भांति यह पूंजी सकारी बांडों, जिनपर तत्काल कोई नकद व्यय नहीं होगा, के रूप में प्रदान की जाएगी। व्याज अदायगियां और शोधन निस्संदेह भावी बजटों पर एक प्रभार होंगे।

23. मैं "बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993, जो विशेष वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना की व्यवस्था करता हूं, को पिछले अगस्त में शीघ्र पारित करने के लिए इस सदन का आभारी हूं। ये न्यायाधिकरण शीघ्र ही प्रचालित हो जाएंगे और बैंकों की बकाया राशि की वसूली में सुधार करने में मुख्य भूमिका अदा करेंगे। मुझे यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता हो रही

है कि रिजर्व बैंक, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण के लिए एक वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना कर रहा है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अग्रग्राह्य करने और उन उधारकर्ताओं, जिन्होंने अन्य ऋणदाता संस्थाओं को उनके बकाया देने में झूक की है, से उन्हें सावधान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक प्रारंभिक सीमा के ऊपर चूककर्ता उधारकर्ताओं के नाम बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को परिचालित करने की व्यवस्था कर रहा है। रिजर्व बैंक ऐसे मामलों, जहां बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुकदमे दायर किए गए हैं, में चूककर्ता उधारकर्ताओं की एक सूची प्रकाशित करेगा। ये दोनों उपाय उधारकर्ताओं में अभिक अनुशासन प्रोत्साहित करेंगे।

24. सरकार पूंजी बाजारों से संबंधित सुधारों को उच्च प्राथमिकता देती है, जिनका उद्देश्य एक कुशल और प्रतिस्पर्धी पूंजी बाजार की रचना करना है तथा इसके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रभावशाली विनियम लागू किए जाएंगे, जिससे निवेशकर्ता को पर्याप्त संरक्षण देना सुनिश्चित हो सकेगा। प्रतिभूति थोटाले के कारण 1992 में एक अस्थायी धक्का लगने के पश्चात् पूंजी बाजार ने शीघ्र ही अपनी जड़ मजबूत कर ली। सेबी अनुमोदन से सार्वजनिक और राइट्स निर्गमों के माध्यम से पूंजी बाजार में जुटाई गई धनराशि 1993-94 के पहले बस महीनों में बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गई, जबकि 1992-93 की उसी अवधि में यह राशि 16,000 करोड़ रुपए तथा 1991-92 के पूरे वर्ष के दौरान यह राशि 6,000 करोड़ रुपए से भी कम थी। इसके अतिरिक्त, बहुत सी भारतीय कंपनियों ने यूरो-इक्विटी निर्गमों तथा विदेशी परिवर्तनीय बांड निर्गमों के माध्यम से विदेशी में भी धनराशि एकत्रित की। सरकार पूंजी बाजार के संपूर्ण आधुनिकीकरण तथा व्यापार प्रणालियों में तेजी से सुधार लाने के लिए कटिबद्ध है, जिसका प्रयोजन सौदों की स्पष्टता और उनके शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करना। स्क्रीन-आधारित व्यापार करने वाले मॉडल राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इस वर्ष के मध्य तक कार्य प्रचालन आरम्भ कर देने की आशा है। इनकी स्थापना से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम और प्रतिभूति (विनियमन) अधिनियम में और संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, ताकि सेबी को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जा सकें।

25. पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में मैंने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की घोषणा की थी, जो बीमा उद्योग का अध्ययन करके भविष्य में उसके विकास हेतु दिशानिर्देश संबंधी अपने सुझाव देगी। बीमा क्षेत्र में सुधार संबंधी उक्त समिति को भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री आर. एन. महोत्रा की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें बीमा क्षेत्र को धीरे-धीरे विनियमन-मुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिससे एक अधिक प्रति-

स्पर्धी और वित्तीय रूप से मजबूत बीमा उद्योग की रचना की जा सके जो एक स्वतन्त्र विनिर्माकारी प्राधिकरण के अन्तर्गत कार्य करे। सरकार इस रिपोर्ट पर अब सक्रिय रूप से विचार कर रही है। मैं इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारी दिशानिर्देश तथा सुधार संबंधी विषयवस्तु के बारे में एक विस्तृत राष्ट्रीय सहमति तैयार करना चाहता हूँ।

26. हमारी अर्थव्यवस्था संबंधी सुधारों की सफलता तथा विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी हेतु कुशल और प्रचुर मात्रा में आधारभूत सेवाओं का होना एक अनिवार्य पूर्व शर्त है। हमारे विद्युत क्षेत्र को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय सक्षमता की समस्या भी शामिल है और यदि हमें लगातार बढ़ती हुई मांग के अनुसार बिजली की आपूर्ति जारी रखनी है तो उक्त समस्या को हल करना होगा। इस क्षेत्र में राज्य विद्युत बोर्डों की कार्य प्रणाली में भारी परिवर्तन करने, शुल्कों को व्यक्तिगत बनाने तथा विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण संबंधी जिम्मेदारियों की पुनः संरचना करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति हमारी बिजली प्रणाली में विस्तृत सुधार लाने के संबंध में विचार कर रही है तथा हमें इस क्षेत्र में बहुत से कड़े निर्णयों का सामना अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा।

27. तेल और गैस क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, ताकि इस क्षेत्र के अन्तर्गत अन्वेषण, विकास, परिणोदन तथा विपणन आदि कार्यों में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। हमारा प्रस्ताव है कि इन उपायों में और अधिक सघनता लाई जाए। कोयला उद्योग में आधुनिकीकरण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार निवेश, मूल्य संरचना तथा वितरण संबंधी नीति ढांचे की समीक्षा कर रही है। दूरसंचार क्षेत्र में भी नये कदम उठाए जा रहे हैं।

28. अब मैं संक्षेप में 1993-94 के संशोधित अनुमानों की ओर आता हूँ।

29. 1993-94 के बजट अनुमानों में 1,31,323 करोड़ रुपए के कुल व्यय का प्रावधान था। इस व्यय के अब 1,43,872 करोड़ रुपए तक पहुँच जाने की संभावना है, यानि इसमें 12,549 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी।

30. चालू वर्ष के बजट अनुमानों में योजनागत व्यय हेतु 41,251 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता का प्रावधान रखा गया था। इस सहायता में 4,775 करोड़ रुपए की वृद्धि करके अब इसे 46,026 करोड़ रुपए किया जा रहा है। बढ़ाई गई इस राशि में 3,493 करोड़ रुपए राज्यों को उनकी योजनाओं के वित्तपोषण हेतु सहायता के रूप में दिए जाएंगे। बड़ी हुई इस राशि का एक बड़ा भाग विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित है। मैंने विशेष श्रेणी वाले राज्यों को अग्रिम योजना सहायता के रूप में 856 करोड़ रुपए की राशि का एक प्रावधान किया है, ताकि वे अपने प्रारम्भिक घाटे

को पूरा कर सके तथा पंजाब को अतिरिक्त विशेष योजना ऋण के रूप में 339 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है, ताकि पंजाब राज्य को उसके पुनरुत्थान संबंधी प्रक्रिया में सहायता मिल सके।

31. केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत, प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 1993 को घोषित नई रोजगार बीमा योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि हेतु चालू वर्ष के प्रावधान में मैंने 320 करोड़ रुपए की वृद्धि की है और यह प्रावधान राशि अब बढ़कर 1,020 करोड़ रुपए हो गई है। इससे राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्वच्छिन्न सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के विरतपोषण तथा प्रशिक्षण और परामर्श संबंधी कार्यों हेतु वित्त पोषण में भी वृद्धि होगी।

32. चालू वर्ष के योजना-भित्त व्यय हेतु 7,774 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता होगी। खाद्य आर्थिक सहायता हेतु 2,200 करोड़ रुपए तथा उर्वरक आर्थिक सहायता हेतु 900 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जानी है। राज्यों की सहायता के रूप में मैं 632 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रख रहा हूँ, ताकि किसानों को नियंत्रण मुक्त उर्वरकों पर रियायत प्रदान की जा सके। रक्षा व्यय हेतु 2,320 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करना भी आवश्यक हो गया है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हम देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं कर सकते। मैं पुलिस के लिए 303 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था कर रहा हूँ। बड़े हुए प्रावधानों में पेंशन के लिए 219 करोड़ रुपए तथा बेहतर संग्रहण के फलस्वरूप राज्यों को लघु बचत संग्रहणों में से उनके हिस्से के रूप में ऋण के तौर पर 500 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

33. सकल कर राजस्व, जिसका बजट में 84,867 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, से अब 8,117 करोड़ रुपए कम प्राप्त होने की संभावना है। इसमें से लगभग 822 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कर प्राप्तियों के कारण है जो 1 दिसम्बर, 1993 से इसकी समेकित निधि में प्राप्त हो रही हैं। इस कारण से भी व्यय में परिणामी कमी आई है। शेष कमी मुख्यतः सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत है। सीमाशुल्क राजस्व भी अपेक्षित राशि से 5,227 करोड़ रुपए कम है जिसका मुख्य कारण यह है कि निर्यातों में इतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी कि आरंभ में आशा थी। अर्थव्यवस्था के अधिक राजस्व उपार्जन वाले कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट आने के कारण उत्पाद शुल्क में 2,001 करोड़ रुपए की कमी आई है। सरकारी उद्यमों में इक्विटी धारिता की विनिवेश संबंधी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में देरी होने के कारण, इस वर्ष संबंधित प्राप्तियां 2,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जब कि इसकी तुलना में बजट अनुमान 3,500 करोड़ रुपए के थे।

34. प्राप्तियों में कमी होने के कारण अधिक उधार लेना अनिवार्य हो गया है। तथापि, मैंने यह सुनिश्चित करने के गंभीर प्रयास किए हैं कि बड़े हुए उधारों से “हाई पावर्ड मनी” में अत्यधिक वृद्धि न हो। इसके स्थान पर हमें यह देखना है कि सरकार बाजार संबद्ध निवेशों के आधार पर उधार ले जैसे कि 364-दिवसीय राजकोषीय ढुंडियां जो कि 1992-93 में आरम्भ की गई थीं। हमने कुछ नए साधन भी शुरू किए हैं जैसे कि शून्य कूपन दर बांड तथा 364-दिवसीय राजकोषीय ढुंडियों की परिपक्वता पर परिवर्तनीय 3-वर्षीय ऋण।

35. वापसी-अदायगियों को घटाने के पश्चात् विदेश ऋण राशि 3,837 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जब कि इसकी तुलना में बजट अनुमान 5,454 करोड़ रुपए है।

36. प्राप्तियों और व्यय में अन्य घट-बढ़ को हिसाब में लेते हुए इस वर्ष के अन्त तक 9,060 करोड़ रुपए का बजट घाटा होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा, जिसके मूल बजट में 36,959 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, अब बढ़कर 58,551 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है। इसलिए, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशतांक के रूप में राजकोषीय घाटा 7.3 प्रतिशत होगा जो कि बजट स्तर पर लगाए गए अनुमान से काफी अधिक है। मैं इस स्थिति से खुश नहीं हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, 1993-94 में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां थीं जिनके कारण अधिक घाटा हुआ। एक निष्क्रिय औद्योगिक क्षमता के कारण मुझे यह चिंता थी कि राजकोषीय घाटे में तेजी से कमी लाने के प्रयास के विपरीत परिणाम निकलते। तथापि, हम बार-बार बड़े राजकोषीय घाटे को बहन नहीं कर सकते। हमें राजकोषीय सुधार के मार्ग पर वापस लौटना चाहिए।

37. अब मैं 1994-95 के बजट अनुमानों की ओर आता हूँ।

38. विकास संबंधी क्रियाकलापों की गति को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता, जो 1993-94 के बजट अनुमान में 23,241 करोड़ रुपए थी, को बढ़ाकर 1994-95 में 27,278 करोड़ रुपए कर दिया गया है जो लगभग 17.4 प्रतिशत वृद्धि की द्योतक है। 1994-95 के 70,141 करोड़ रुपए वाली केन्द्रीय योजना के कुल परिव्यय में से 39 प्रतिशत भाग को बजटीय सहायता से वित्तपोषित किया जाएगा जब कि 1993-94 के बजट अनुमान में यह सहायता 36 प्रतिशत थी। केन्द्रीय योजना परिव्यय के शेष भाग को केन्द्रीय सरकार के उद्यमों के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

39. मैं राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को 1994-95 के लिए 19,304 करोड़ रुपए की राशि योजना सहायता के रूप में प्रदान कर रहा हूँ जब कि 1993-94 के बजट अनुमान में यह राशि 18,010 करोड़ रुपए थी। केन्द्रीय

और राज्य योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार के बजट में से कुल बजटीय सहायता में 13 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी और 1993-94 के बजट अनुमान में 41,251 करोड़ रुपए की तुलना में 1994-95 के लिए यह सहायता राशि 46,582 करोड़ रुपए रखी गई है।

40. केन्द्रीय योजना हेतु बढ़ा दी गई बजटीय सहायता मुख्यतः ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा महिला और बाल विकास तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के उच्च परिव्यय को पूरा करने के लिए प्रदान की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजन और पूंजी निर्माण की महत्वपूर्ण आवश्यकता तथा ग्रामीण निर्धनता को तेजी से कम करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के परिव्यय, जो कि 1993-94 के बजट अनुमान में 5,010 करोड़ रुपए था, को बढ़ाकर 1994-95 में 7,010 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत की भारी वृद्धि का द्योतक है। माननीय सदस्यों को याद होना कि 1992-93 के बजट अनुमान में ग्रामीण विकास के लिए, 3,100 करोड़ रुपए का आवंटन रखा गया था। दो वर्षों में हमने इस प्रावधान को दुगुना से भी अधिक कर दिया है। 15 अगस्त, 1993 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित नई रोजगार बीमा योजना, जिसे 1752 निर्धारित ब्लकों में कार्यान्वित किया जा रहा है, के लिए 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जब कि 1993-94 में यह राशि 600 करोड़ रुपए थी। इसी प्रकार, जवाहर रोजगार योजना के लिए आवंटन राशि को 1993-94 के बजट अनुमान में 3,306 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 3,855 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अनुमान है कि 1994-95 में 1150 मिलियन श्रम दिवसों का सृजन किया जाएगा। मैंने राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना सहित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के लिए आवंटन को भी वर्ष 1994-95 में 150 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है।

41. उद्योग, सेवा और व्यवसाय उद्यमों के माध्यम से 7 लाख छोटे उद्यमों की स्थापना द्वारा देश में उस लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम. आर.वाई.) 2 अक्टूबर, 1993 को आरम्भ की गई थी। इस योजना में 1993-94 के दौरान शहरी क्षेत्रों और 1994-95 से आगे के दौरान पूरे देश को शामिल करने का विचार है। इसके लिए 1994-95 में 145 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

42. कृषि के लिए 1994-95 में परिव्यय 2,005 करोड़ रुपए होगा। उद्यान विकास पर काफी धन दिया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत आवंटन में 42 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे बजट अनुमान 1993-94 में 130 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 184 करोड़ रुपए किया गया है। त्रिप सिंचाई में प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ाने की एक

बड़ी योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके लिए 1994-95 के दौरान 45 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ परिव्यय रखा गया है।

43. आठवीं योजना में हमने मानव संसाधनों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। इस क्षेत्र के लिए अधिकतर परिव्यय राज्यों की आयोजनाओं में शामिल है। केन्द्रीय आयोजना में शिक्षा के लिए परिव्यय में 17.6 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 1994-95 में 1,541 करोड़ रुपए किया गया है। प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके वास्ते परिव्यय को 1993-94 के बजट अनुमान में 442 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 523 करोड़ रुपए किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए आवंटन को 1993-94 के बजट अनुमान में 159 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 209 करोड़ रुपए किया गया है। उच्च शिक्षा की प्रणाली में पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता का उन्नयन करने के लिए विशेष आवंटन किये गये हैं। एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और असम में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

44. स्वास्थ्य के लिए परिव्यय में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 1993-94 के बजट अनुमान में 483 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 578 करोड़ रुपए किया गया है। अन्धत्व के नियंत्रण के लिए नवीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम अगले वर्ष से कार्यान्वित किया जाएगा। कुष्ठ-निवारण कार्यक्रम के लिए आवंटन को 1993-94 के बजट अनुमान में 35 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 94 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एड्स का नियंत्रण और उपचार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस संबंध में 1994-95 में 83 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई व्यवस्था की गई है।

45. परिवार कल्याण विभाग के लिए परिव्यय को भी 1993-94 के बजट अनुमान में, 1,270 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 1,430 करोड़ रुपए किया गया है।

46. विशिष्ट योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता सहित वर्ष 1994-95 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 982 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम को केन्द्रीय सरकार द्वारा शेष पूंजी अंशदान 1993-94 के बजट अनुमान में 53 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 76 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

47. आधारभूत ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दूर-संचार, रेलवे और परिवहन, सभी से संबंधित आयोजना परिव्ययों

में वृद्धि की गई है। विद्युत क्षेत्र के लिए आयोजना परिव्यय को 1993-94 के बजट अनुमान में 7,461 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 8,464 करोड़ रुपए किया गया है और इसी कुल राशि के अन्तर्गत विद्युत क्षेत्र के लिए बजट सहायता को 1993-94 के बजट अनुमान में 2,445 करोड़ रुपए से 27 प्रतिशत अधिक बढ़ाकर 1994-95 में 3,117 करोड़ रुपए किया गया है। दूर-संचार सेवाओं के लिए आयोजना परिव्यय को 1993-94 के बजट अनुमान में 6,321 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 7,246 करोड़ रुपए किया गया है। सड़कों के लिए परिव्यय को 1993-94 के बजट अनुमान में 593 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 665 करोड़ रुपए किया गया है। हमने रेलवे को बजट सहायता में भी 20 प्रतिशत वृद्धि करके 1993-94 के बजट अनुमान में 960 करोड़ रुपए से 1994-95 में 1,150 करोड़ रुपए किया है। दीर्घवृद्धि विकास को स्थिर रखने के लिए आधारभूत सेवाओं की लागत वसूली को अधिक कारगर बनाना है। आधारभूत क्षेत्र में निवेश को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आन्तरिक और बजट-बाह्य संसाधनों द्वारा अधिकाधिक वित्तपोषित करना है।

48. हमारी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने और इसे विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए परिव्यय में 19 प्रतिशत वृद्धि करके इसे 1993-94 के बजट अनुमान में 189 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994-95 में 225 करोड़ रुपए किया गया है।

49. अगले वर्ष के लिए कुल आयोजना-भिन्न व्यय चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 97,846 करोड़ रुपए की तुलना में 1,05,117 करोड़ रुपए किया गया है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान एक प्रमुख कारक की ओर आकर्षित करा चाहता हूँ जो कि वर्ष-प्रतिवर्ष आयोजना-भिन्न व्यय में काफी वृद्धि में योगदान देता रहा है और वह व्याज का बोझ है। अगले वर्ष के लिए व्याज अदायगियों के वास्ते 46,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह चालू वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 8,000 करोड़ रुपए अधिक है, जबकि कुल आयोजना-भिन्न व्यय में 15,045 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। माननीय सदस्य जानते ही हैं कि व्याज बोझ का एक बड़ा हिस्सा हमें विगत से परस्परा में मिला है और यह सरकारी उधार के लगातार ऊँचे स्तर के कारण बढ़ता ही जा रहा है। व्याज अदायगियों को केवल तभी कम किया जा सकता है यदि हम सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं या राजकोषीय घाटे में चरणबद्ध कटौती का कोई कार्यक्रम कार्यान्वित कर सकें। यह केवल तभी वास्तविकता बन सकती है यदि हमारी कर-प्रणाली अधिक उत्साही बन जाए, हमारे सरकारी उद्यम अधिक आन्तरिक संसाधन पैदा कर सकें और हम आर्थिक सहायताओं पर व्यय को कम कर सकें। सरकारी उद्यमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश और विशुद्धतः ऋण कम करने के लिए बिन्नी आय का एक हिस्सा निर्धारित करने के वास्ते एक निर्भीक कार्यक्रम काफी सहायक होगा।

619 GI/94-2

50. आयोजना-भिन्न व्यय में रक्षा एक अन्य महत्वपूर्ण संघटक है। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। इसलिए, मैं रक्षा के लिए 1993-94 के बजट अनुमान 19,180 करोड़ रुपए, जो संशोधित अनुमान में स्वतः बढ़ कर 21,500 करोड़ रुपए हो गया था, उसकी तुलना में 23,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं खाद्य राज-आर्थिक सहायता और उर्वरक राज-आर्थिक सहायता प्रत्येक के लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं ऋणों को ऋण राहत योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दीय राशि के लिए 341 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैं विदेशी मुद्रा अतिवासी खाता योजना पर विनिमय हानि देयता के सरकार के पूर्वानुमान के कारण 365 करोड़ रुपए के निवल व्यय की व्यवस्था कर रहा हूँ जिसका पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वहन किया जाता था।

51. व्याज अदायगियों और रक्षा के लिए आयोजना-भिन्न व्यय के वास्ते अगले वर्ष के बजट में की गई व्यवस्था चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों में वास्तव में 2,729 करोड़ रुपए कम है।

52. प्राप्ति पक्ष में विद्यमान कर स्तरों पर सकल कर-राजस्व 87,136 करोड़ रुपए बैठता है। अगले वर्ष राज्यों का करोड़ों में हिस्सा चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 22,244 करोड़ रुपए की तुलना में 24,394 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वापसी-अदायगियों को घटाकर विदेशी ऋण चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 3,837 करोड़ रुपए की तुलना में 4,279 करोड़ रुपए बैठता है।

53. परिपक्व होने वाली देयताओं को हिसाब में लेते हुए अगले वर्ष में निवल लघु बचत संग्रहण चालू वर्ष के उसी स्तर अर्थात् 6,000 करोड़ रुपए बैठते हैं। मैं सरकारी क्षेत्र की इक्विटी की बिक्री से अवस्फीतिकारी संसाधन जुटाने की नीति को जारी रखते हुए विनिवेश से प्राप्ति के रूप में अगले वर्ष के लिए 4,000 करोड़ रुपए का ऋण ले रहा हूँ। कुल प्राप्ति 1,45,699 करोड़ रुपए और कुल व्यय 1,51,699 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिससे 6,000 करोड़ रुपए का अन्तर शेष रहेगा।

भाग II

54. अब मैं वर्ष 1994-95 के कर संबंधी प्रस्तावों पर आता हूँ। इस वर्ष, मैं अप्रत्यक्ष करों के प्रस्तावों से शुरुआत करूँगा।

55. पिछले कई वर्षों से हमारी अप्रत्यक्ष कर संरचना उच्च और एकाधिक दरों की भूलभुलैया बन कर रह गई है, जिसमें बहुत सी रियायतें और एक ही उत्पाद के लिए विभिन्न प्रयोगों और प्रयोगकर्ताओं के लिए अलग-अलग दरें लागू होती हैं। इससे अनावश्यक दुरुहता उत्पन्न हो गई है,

जिसके कारण प्रशासनिक दुरुपयोग, बढ़ते हुए मुकदमों तथा अनिश्चित आर्थिक प्रभाव जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। इन सब से कर संबंधी आधार और प्रणाली की प्रभावकारिता काफी कम हुए हैं तथा इसमें गंभीर आर्थिक विकृतियां पैदा हुई हैं। सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दोनों से संबंधित भेरे प्रस्तावों का लक्ष्य कर संरचना को सरल बनाना तथा कराधान की दरों को संतुलित बनाने की प्रक्रिया को जारी रखना है।

56. यद्यपि, पिछले तीन बजटों में सीमाशुल्क दरों में भारी कमी की गई हैं, लेकिन, इनमें और कमी किए जाने की आवश्यकता है, जिससे भारतीय उद्योग को कच्ची सामग्री और पूंजीगत वस्तुएं उचित लागतों पर मिलती रहें तथा उद्योग को दिये जाने वाले संरक्षण के अनुचित उच्च स्तर को भी कम किया जा सके। इसके साथ ही, शुल्क में कमी के मानदण्ड को इस तरह से संशोधित किया जाना आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इससे हमारे देश में उन्हीं उत्पादों के उत्पादकों पर अनुचित दबाव न पड़े। इस कर संरचना में, सीमाशुल्क सुधारों संबंधी भेरे प्रस्तावों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

*सीमाशुल्क की उच्च दरों में और कटौती करना,

*इस्पात और रसायनों जैसी मुख्य कच्ची सामग्रियों पर शुल्क में भारी कमी करना;

*निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर सीमाशुल्क में कमी करने के साथ-साथ अन्य प्रोत्साहन भी प्रदान करना, जिससे पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग को सहायता मिल सके ;

*कच्ची सामग्री तथा अवयवों पर आयात शुल्क की दरों जो कि परिष्कृत उत्पादों की शुल्क दरों से अधिक हैं, से संबंधित विसंगतियों को कम करना अथवा समाप्त करना;

*एक जैसे उत्पादों पर एक जैसी शुल्क दरों को एकीकृत करने का सुव्यवस्थित प्रयास करना, जिससे आर्थिक यौषितकीकरण हो और विवादों के वर्गीकरण के विस्तार में कमी आए,

*अधिसूचनाओं में जारी काट-छांट कर उनकी वर्तमान संख्या को लगभग आधी करना, जिनमें समापन उपयोग छूट भी सम्मिलित है, इस प्रकार विवेकाधीन शक्तियों और विवादों की संभावनाओं को कम करना।

57. मैं सीमाशुल्क की उच्च दरों को 85 प्रतिशत से घटाकर 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। लेकिन, यात्री समान तथा शराब पर शुल्क की मौजूदा उच्च दरें लागू रहेंगी।

58. हमारी प्रतिस्पर्धा और निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत वस्तुओं का उचित लागत पर उपलब्ध होना

आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि अत्यधिक संभावनाओं वाले हमारे स्वदेशी पूंजीगत वस्तु उद्योग को कर संरचना में विसंगतियों के कारण तुलनात्मक रूप से कोई हानि न पहुंचे। इन दोनों उद्देश्यों का दृष्टि से, मैं निम्नलिखित उपायों के पैकेज का प्रस्ताव करता हूं :—

(क) मैं परियोजना आयातों तथा सामान्य पूंजीगत वस्तुओं पर से मूल सीमाशुल्क को 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। परियोजना आयातों की यह सुविधा पत्तन विकास को शामिल करने के लिए प्रदान की जा रही है, इस सबसे भारतीय उद्योगों में निवेश और आधुनिकीकरण की लागत को कम करने में सहायता मिलेगी। सहायक पुर्जों, चाहे वे मूल उपस्कर के पुर्जों हों अथवा अतिरिक्त पुर्जों हों, पर आयात शुल्क की वर्तमान दरों, जो कि इस समय 25 प्रतिशत से 85 प्रतिशत के बीच अलग-अलग हैं, को घटाकर 25 प्रतिशत किया जा रहा है। उर्वरक परियोजनाओं और विद्युत परियोजनाओं पर आयात शुल्क बिना किसी समतुल्य शुल्क के क्रमशः शुन्य दर और 20 प्रतिशत दर पर जारी रहेंगी।

(ख) पूंजीगत वस्तुओं के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं का निरन्तर यह तर्क रहा है कि यदि घरेलू पूंजीगत वस्तुओं को आयातों के साथ परिस्पर्धा करनी है, तब पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं पर लगे उत्पाद शुल्क का प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। मैं इस मांग को स्वीकार करता हूं।

(ग) इसके साथ ही मैं पूंजीगत वस्तुओं को 'मोडवाट' संबंधी लाभ प्रदान करता हूं, जिससे स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं पर अदा किया गया उत्पाद शुल्क अथवा आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर अदा किया गया प्रतिकारी शुल्क संबंधी ऋण एक ही बार उपलब्ध हो। यह मांग भारतीय उद्योग के सभी क्षेत्रों की तरफ से काफी समय से प्राप्त होती रही है।

(घ) मशीनी औजारों पर इस समय 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत की विभिन्न दरों से शुल्क लगता है। मेरा प्रस्ताव इस संरचना को सरल बना कर शुल्क को 35 प्रतिशत अथवा 45 प्रतिशत कर देने का है।

(ङ) परिष्कृत पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क में कमी करने के पश्चात यह आवश्यक है कि इस्पात, जो कि एक महत्वपूर्ण निर्विण्ट है, पर से सीमा-

शुल्क को भी कम किया जाए। मैं इस्पात पर मौजूदा 75 से 85 प्रतिशत को सीमाशुल्क दर को कम करके 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। ताँबा, जस्ता तथा सीसे जैसी मुख्य अथवा धातुओं के बुनियादी रूपों पर आयात को एकसमान करके 50 प्रतिशत की दर पर निर्धारित किया जा रहा है। इन प्रस्तावों से, अर्थव्यवस्था में निवेश को एक मजबूत बल मिलेगा तथा विशेष रूप से स्वदेशी पूंजीगत वस्तु उद्योग को सहायता मिलेगी।

59. स्वदेशी धातु निर्माताओं की सहायता हेतु, सभी अयस्कों और सान्द्रों पर सीमाशुल्क को कम करके 10 प्रतिशत की एक ही दर पर निर्धारित किया जा रहा है। गौण इस्पात क्षेत्र हेतु निविष्टियों को लागत को कम करने के लिए मैल्टिंग स्क्रैप पर आयात शुल्क 12.5 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत तथा लोह अयस्क गुटिकाओं पर 15 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

60. हमारे चमड़ा उद्योग जो निर्यात संबंधी आय का एक मुख्य अर्जक है तथा जिसमें रोजगार के गहन अवसर होते हैं, के निर्यात संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, मैं इस उद्योग में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी की बहुत सी मदों तथा कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क, जो कि इस समय 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच है, को कम करके, बिना किसी समतुल्य शुल्क के 20 प्रतिशत की एक दर पर लाने का प्रस्ताव करता हूँ।

61. तीव्र आर्थिक विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक तथा दूरसंचार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इनसे अतिरिक्त रोजगार और निर्यातों, दोनों ही के सृजन में भारी योगदान मिलता है। इन क्षेत्रों की शुल्क संरचना को युक्तियुक्त बनाने के लिए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:—

(क) कंप्यूटर के पुर्जों पर आयात शुल्क को 80 प्रतिशत से कम करके 50 प्रतिशत किया जा रहा है। विशिष्ट संघटकों पर शुल्क 50 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत तथा विशिष्ट अलग पुर्जों (पीस-पार्ट्स) पर शुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया जा रहा है। एप्लीकेशन साफ्टवेयर पर से आयात शुल्क 85 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत किया जा रहा है।

(ख) दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मैं ऐसे उपकरणों के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक-भिन्न पुर्जों पर आयात शुल्क को 50 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत तथा ऑप्टिकल फाइबर पर शुल्क 85 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिससे देश में ही ऑप्टिकल फाइबर के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

62. हमारे स्वदेशी घड़ी उद्योग के विकास की भारी संभावनाएँ हैं। हमारा यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बने, इसके लिए मैं इस उद्योग से संबंधित मशीनरी की कुछ मदों पर आयात शुल्क की दर, जो इस समय 50 प्रतिशत है, को घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके साथ ही, घड़ी उद्योग से संबंधित कुछ संघटकों तथा कच्ची सामग्री पर मौजूदा शुल्क दरों को 70 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से घटाकर क्रमशः 25 प्रतिशत और 20 प्रतिशत करने का करता हूँ।

63. चिकित्सा संबंधी उपस्कर से संबंधित आयात शुल्क की मौजूदा संरचना काफी जटिल है तथा बहुत से मामलों में तो प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण काफी समय लग जाता है। स्वदेशी उद्योग भी आयातित उपस्कर के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि, यह उपस्कर अब नामित प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अस्पतालों को बिना शुल्क के उपलब्ध हो जाता है। उपरोक्त बाधाओं को दूर करने के लिए, मेरा प्रस्ताव है कि घर्माघर्ष अस्पतालों हेतु प्रमाणपत्र की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए तथा बिना किसी प्रतिकारी शुल्क के 15 प्रतिशत की शुल्क दर से निविष्ट चिकित्सा उपस्करों के मुक्त आयात की अनुमति प्रदान कर दी जाए। ऐसे उपस्करों की सूची पृथक् रूप से तैयार की जा रही है तथा गुण-दोष के आधार इस सूची को बढ़ाया भी जा सकता है। तथापि, सरकारी अस्पतालों तथा सभी निविष्ट जीवन रक्षक और दृष्टि रक्षक उपस्करों का शून्य दर पर आयात करना जारी रखा गया है। अन्य चिकित्सा उपस्करों पर आयात शुल्क की मौजूदा दर को 85 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है। उनके विनिर्माण संबंधी संघटकों का आयात 15 प्रतिशत सीमाशुल्क की दर पर करने की अनुमति दी जाएगी। अंतर से स्वदेशी उद्योग द्वारा चिकित्सा उपस्करों का निर्माण करने में सहायता मिलेगी।

64. कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित आयात शुल्क संरचना को सरल बनाया जा रहा है। कच्चे पेट्रोल और कोयले पर अब क्रमशः 1500/- रुपए प्रति मीट्रिक टन और प्रतिशत के स्थान पर अब 35 प्रतिशत की दर से आयात शुल्क लगाया जाएगा कोयले पर शुल्क 85 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया जा रहा है। एल.पी.जी. और अन्य पेट्रोलियम गैसों पर 15 प्रतिशत की दर से आयात-शुल्क लगेगा। नेप्था और कैरोसिन पर बुनियादी सीमाशुल्क से छूट जारी रहेगी। अन्य पेट्रोलियम पदार्थ पर 30 प्रतिशत आयात शुल्क लगेगा। इन परिवर्तनों से उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के प्रशासनिक मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

65. रसायनों से संबंधित वर्तमान आयात शुल्क ढाँचे में बुनियादी संभरक सामग्रियों (फीड-स्टॉक) के लिए 15 प्रतिशत शुल्क की कम दर और तैयार-गुदा रसायनों के लिए 85 प्रतिशत की उच्च दर की व्यवस्था की गई

है। दरों के समग्र विस्तार की उच्च दर को 65 प्रतिशत तक घटाकर कम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, डी. एम. डो., पी. टी. ए. और एम. ई. जी. पर शुल्कों को 70 प्रतिशत से कम करके 60 प्रतिशत किया जा रहा है और एक्सलिस तथा टोल्यून जैसे मध्यवर्तियों पर शुल्कों को 40 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत किया जा रहा है। बुनियादी संभरक सामग्रियों (फीड-स्टॉक) के लिए 15 प्रतिशत की दर अपरिवर्तित रखी गई है।

66 फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनेक कच्ची सामग्रियों पर आयात शुल्क, जो कि इस समय 85 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच हैं, उन्हें 50 प्रतिशत या 25 प्रतिशत की दो दरों तक कम किया जा रहा है। कुछ मामलों में ड्रग मध्यवर्तियों के घरेलू विनिर्माताओं के हितों की सुरक्षा करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आयात शुल्क में कुछ उर्ध्वगामी संशोधन किया गया है।

67. हालांकि, इस संबंध में मुझे कोई संदेह नहीं है कि सोमाशुल्कों में चरणबद्ध कटौती हमारे उद्योग के दीर्घ-वधिक हित के लिए अनिवार्य है, मुझे कुछ आयातित वस्तुओं की कृत्रिम तौर पर कम मूल्यों पर भंडारण करने संबंधी कुछ उद्योगों की चिन्ता की भी पूरी जानकारी है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी भंडारणरोधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें और मजबूत बनाया जाएगा।

68. मैं अब केन्द्रीय उत्पाद संबंधी प्रस्तावों पर आता हूं।

69. इस बजट में हमारी कर प्रणाली को आधुनिक बनाने के हमारे कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उत्पाद कर ढांचे में भारी सुधार करने का प्रस्ताव है। इस पुनर्संरचना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

—मोडवाट को पूंजीगत वस्तुओं और पेट्रोलियम पदार्थों पर लागू करना,

—अधिकतर उत्पाद कराधान को निर्दिष्ट से मूल्यानुसार दरों में अंतरित करना, जिससे राजस्वों में काफी अधिक वृद्धि सुनिश्चित होगी ;

—मूल्यानुसार कर दरों की कुल संख्या में कमी करके वर्तमान संख्या का लगभग आधा करना, जो कि सरलता और सुस्पष्टता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा,

—दरों को कम करने की प्रक्रिया को जारी रखना, जब भी ये अनावश्यक रूप से उच्च स्तरों पर हों;

—जहां तक संभव हो, एक समान वस्तुओं के लिए एक समान दरें लागू करना। इससे वर्गीकरण समस्याएं, भ्रष्टाचार की संभावना और अत्यधिक मुकदमेबाजी समाप्त हो जाएगी।

—जटिल मूल्य सूची की प्रक्रिया को समाप्त करना;

—विशेष छूट अधिकृतियों की संख्या में कमी करके उन्हें लगभग आधा करना।

70. इन कदमों से विनिर्माण उत्पादन और रोजगार वृद्धि का संवर्धन होगा और कर प्रणाली सरल बनेगी तथा विवेकाधिकार कम होंगे और भ्रष्ट वर्गीकरण, विवादों और अपव्यय की संभावना भी कम होगी। इससे राजस्व नभ्यता बढ़ेगी और अंततः मूल्यवर्धित कर (वैट) अपनाए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

71. अंततः, भारी पुनर्संरचना में अनेक उत्पादों के लिए अनेक दरों में परिवर्तन शामिल होते हैं, क्योंकि उत्पादों को कम दर वाली श्रेणियों में पुनः वर्गीकृत करना होता है। इसके अलावा, मोडवाट लागू करने के कारण राजस्व हानि के लिए प्रतिपूर्ति करने के वास्ते कुछ मामलों में शुल्क दरों को समायोजित किया गया है। फिर भी, हमने सुनिश्चित किया है कि आम खपत की वस्तुओं पर अधिक करों का बोझ नहीं डाला जाए। उदाहरणार्थ, अनेक वस्तुओं जैसे कि हथकरघा उत्पाद, बिना ब्रांड की ड्रग्स, घरेलू बिजली के बल्ब, बाइसिकल, शिशु आहार, खाना पकाने का तेल, मसाले, जैम, जैली, सॉसिज, चाय और फांकी पर पूरी छूट जारी है। इस बात को ध्यान में रखा गया है कि कुछ वस्तुओं के मूल्य न बढ़ाए जाएं, उदाहरणार्थ चीनी, माचिस और वनस्पति। इससे आम आदमी की उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

72. अब मैं विशेष रुचि के कुछ प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख करना चाहूंगा।

73. महोदय, इस सदन को याद होगा कि मोडवाट स्कीम 1986 में आरंभ की गई थी। बाद में इसके विस्तार ने निविष्टि करों के क्रमिक प्रभाव को कम करने में बहुत सहायता की है। लेकिन, इसका विस्तार अभी अधूरा है। पेट्रोलियम पदार्थों, वस्त्र, माचिस, तम्बाकू के उत्पादों और पूंजीगत वस्तुओं को इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया था। इस स्कीम को अधिक व्यापक बनाने के लिए उद्योग को ओर से लगातार मांग की जाती रही है। मैं अब मोडवाट स्कीम को दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों, यथा पूंजीगत वस्तुओं और पेट्रोलियम पदार्थों पर लागू करने का प्रस्ताव करता हूं।

74. मैं पेट्रोलियम पदार्थों के ढांचे को सुकृतिपुस्त बनाने का प्रस्ताव करता हूं। इस समय उत्पाद शुल्क दरें निर्दिष्ट हैं। अन्ततः उपयोग के अनुसार अनेक छूट उपलब्ध हैं। मैं वर्तमान निर्दिष्ट दरों के स्थान पर, मोडर डिस्ट जिस पर कि 20 प्रतिशत शुल्क लगेगा, को छोड़कर, सभी पेट्रोलियम पदार्थों पर 10 प्रतिशत की एक समान मूल्यानुसार दर प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

अन्तर उद्योग छूटें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तथापि, उर्वरक उद्योग के लिए वर्तमान रियायतें जारी रखी गई हैं। इन परिवर्तनों से इन भरो के प्रशासित मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

75. सूती और हस्त-निर्मित फैब्रिक्स के लिए वर्तमान शुल्क ढांचा मूलानुसार और निदिष्ट दरों का निश्चय है। मैं इस समय लागू अतर्गित निदिष्ट और मूलानुसार दरों के स्थान पर केवल 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की मूलानुसार दरें लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

76. फाइबरों और यार्न पर वर्तमान उत्पाद शुल्क संरचना जटिल है और विभिन्न प्रकार के यार्न और फाइबरों के लिए अलग-अलग निदिष्ट दरें निर्धारित की गई हैं। इसके कारण सही शुल्क देयता निर्धारित करने के लिए नमूनों का बार-बार परीक्षण करना पड़ता है। वर्गीकरण की सभी समस्याओं का निराकरण करने और विभिन्न फाइबर तथा यार्न के बीच उत्पाद शुल्क को निष्क्रिय बनाने के लिए मैं सभी फाइबर और ब्लेंडेड या काटे गए यार्न पर 20 प्रतिशत का एकसमान उत्पाद शुल्क लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, सूती यार्न पर वर्तमान जटिल और यार्न के फाऊंड के अनुसार विभिन्न निदिष्ट दरों के स्थान पर केवल 5 प्रतिशत की दर पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। जहां तक फिलामेंट यार्न का संबंध है, राजस्व प्राप्त एक समान उत्पाद शुल्क की दिशा में बढ़ने से रोकती है। इसलिए, मैंने पोलि-एस्टर फिलामेंट यार्न के लिए 60 प्रतिशत, नाईलोन और पोलिप्रोपलीन यार्न के लिए 30 प्रतिशत की और विस्कांस फिलामेंट यार्न के लिए 15 प्रतिशत की दर पर मूलानुसार शुल्क दर लगाने का प्रस्ताव किया है। ऑर्गेनिक यार्न के लिए 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की कम दरें निर्धारित की गई हैं। मोडवाट स्कीम फाइबर से बने यार्न पर लागू की जा रही है, इसके साथ ही मोडवाट सभी यार्न पर लागू हो जाएगी। ये परिवर्तन मुख्यतः ढांचे का सरलीकरण और सुविधाकरण है। सामान्य में कमी करने के साथ ही ये इस क्षेत्र में मूल्यों को संतुलित करने में सहायक होने चाहिए।

77. मैं एल्फ़ीनिवम को छोड़कर, जिसके लिए अब शुल्क 25 प्रतिशत की तुलना में 20 प्रतिशत होगा, सभी धातुओं पर 15 प्रतिशत का एकसमान शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, पिंग आयरन और लोहे के कुछ अन्य उत्पादों के लिए 10 प्रतिशत का कम शुल्क लागू रहेगा।

78. ड्रम पर उत्पाद ढांचा अनुसूची I, अनुसूची II और अन्य ड्रम के बीच अन्तर दर्शाता है। अनुसूची I की ड्रम जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए हैं और मूल्य निर्धारणार्थ हैं, उन्हें उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त है। यह व्यवस्था जारी रहेगी। अनुसूची II की ड्रम

के एकल नुस्खों पर 10 प्रतिशत का उत्पन्न शुल्क लगता है, जबकि अन्य ब्रांड वाली ड्रम पर 15 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगता है। मैं इन दोनों का एकीकरण करते हुए 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं आयुर्वेदिक ब्रांड वाली और होम्योपैथिक दवाइयों तथा अन्य वैकल्पिक प्रणालियों की दवाइयों पर 10 प्रतिशत का साधारण उत्पाद शुल्क भांति करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस समय बड़े ड्रम उत्पादक बल्क ड्रम पर 5 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क के कारण, जो कि बहुत कम है, मोडवाट के पूरे लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है ताकि वे पूरे लाभ उठा सकें। तथापि, बिना ब्रांड वाली ड्रम पर उत्पाद शुल्क से छूट जारी रहेगी।

79. विभिन्न रसायनों और डाई, रंग-रोगन, चर्म-शोधन मिश्रण आदि जैसे रसायन आधारित उत्पादों के लिए शुल्क ढांचे को सरल बनाने की दृष्टि से मैं ऐसे उत्पादों पर 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच की वर्तमान दरों के स्थान पर 20 प्रतिशत की एक समान दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। प्रमुख बल्क प्लास्टिकों, सिथेटिक रंग-रोगनों और डिटर्जेंट्स पर इस समय लागू 35 प्रतिशत की दर के स्थान पर 30 प्रतिशत की एक समान दर लागू होने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

80. कागज का शुल्क ढांचा शून्य, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 30 प्रतिशत की मूलानुसार दरों, त्रिशिष्ट दरों और त्रिशिष्ट-सह-मूलानुसार दर के कारण जटिल है। इसे अब कागज पर शुल्क की सामान्य दर 20 प्रतिशत करके, अथवासी कागज, निखन सामग्री आदि के लिए शून्य, कागज आधारित परतों और फर्श आवरकों के लिए 30 प्रतिशत और गैर-परम्परागत कच्ची सामग्रियों से निमित कागज के लिए 10 प्रतिशत अथवा 15 प्रतिशत दर रखकर सरलीकृत किया जा रहा है। मैं गैर-परम्परागत कच्ची सामग्रियों का प्रयोग करने वाले कागज की मिलाई को वर्तमान में उपलब्ध छूट की सीमा बढ़ा रहा हूँ। वर्तमान में यह छूट किसी विनिर्माता की एक से अधिक फैक्टरी से कागजों की स्वीकृति को एक साथ करने लाभ को सामित कर देती है। मैं अब इसे पृथक रूप से प्रत्येक फैक्टरी द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए इस रियायत की अनुमति दे रहा हूँ।

81. प्रयाधन-सामग्री और इसके समान व्यक्तिगत देखभाल के उत्पादों पर लागू 70 प्रतिशत की शुल्क दर उन मदों के लिए बहुत अधिक है, जो अब लगातार ग्राम लोगों की खपत का हिस्सा बनती जा रही हैं। इसलिए, इस दर को घटाकर 50 प्रतिशत किया जा रहा है।

82. मैं सामान्य लघु उद्योग छूट स्कीम में भी कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव कर रहा हूँ। वर्तमान में, केवल पंजीकृत इकाइयां ही 75 लाख रुपये तक के स्वीकृति मूल्य की रियायत प्राप्त करने की पात्र हैं। अपंजीकृत इकाइयों केवल

30 लाख रुपए तक छूट प्राप्त कर सकती हैं। मैं इस अंतर को मिटा देने का प्रस्ताव करता हूँ, ताकि लघु उद्योग इकाइयाँ, चाहे वे पंजीकृत हैं अथवा नहीं, इसका ध्यान दिए बिना उनको दी जाने वाली छूट प्राप्त कर सकें। यह लघु उद्योग की एक मुख्य मांग पूरी करेगा। लघु उद्योग स्कीम की सीमा कुछ लोहा इस्पात और ताम्बा उत्पादों सहित कई अतिरिक्त मदों को शामिल करने के लिए विस्तारित की जा रही है।

83. मौजूदा स्कीम के अन्तर्गत, अन्य इकाई के ब्राण्ड नाम के अधीन वस्तु विनिर्माण कर रही लघु इकाई केवल तभी शुल्क की रियायत पाने की हकदार है, यदि ब्राण्ड नाम किसी बड़ी इकाई का नाम नहीं हो। बड़ी इकाइयों द्वारा उनके ब्राण्ड नामों की छोटी इकाइयों के नाम से पंजीकृत करके शुल्क के भुगतान से बचने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इससे लघु विनिर्माता को स्वयं अपना ब्राण्ड संबंधित करने की अनुमति नहीं मिलती। देश में अन्तर्राष्ट्रीय ब्राण्ड नामों की शुरुआत से, घरेलू उद्योग के हित में स्कीम के दुरुपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है। इसलिए, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि अन्य विनिर्माता के ब्राण्ड नाम वाली वस्तुओं की स्वीकृति पर शुल्क से छूट का लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

84. लघु उद्योगों की निरंतर मांगों में से एक, उन्हें शुल्क अथवा करने की अनुमति देना रही है, यद्यपि, वे अन्यथा छूट के हकदार हैं, क्योंकि यह उनके ग्राहकों को 'मोडबाट' श्रृण के लाभ का दावा करने का पात्र बना देगा। इस अनुरोध में काफी अच्छाई है और मैं उन्हें, जो इसका प्रयोग करना चाहेंगे, इसका विकल्प देने का प्रस्ताव करता हूँ।

85. यह स्मरणीय है कि पिछले बजट में, जहाज-तोड़ने वाले उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए जहाजों पर मूल सीमाशुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क देय था। जहाज को तोड़ने से प्राप्त लौह धातुओं को परिणामतः उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त थी। जहाजों के तोड़ने पर प्रतिकारी शुल्क की देयता के संबंध में कुछ विवाद रहे हैं। इन विवादों को दूर करने के लिए मैं जहाजों के तोड़ने को प्रतिकारी शुल्क छूट देने और सदृश रूप से मूल सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत पर समायोजित करने का प्रस्ताव करता हूँ। जहाज-तोड़ने वाले उद्योग के लिए ऐसी टूट से प्राप्त सभी सामग्रियों को भी उत्पाद शुल्क से छूट देना प्रस्तावित है, ताकि जहाज को तोड़ने के क्रियाकलाप पूरी तरह से उत्पाद शुल्क निर्यवण से परे हों।

86. चूंकि मैं सिगरेटों पर शुल्कों की विशिष्ट दरें जारी रख रहा हूँ और मूल्यों में वृद्धि के बावजूद ये पिछले दो वर्षों से अपरिवर्तित रही हैं मैं सिगरेटों पर शुल्कों को लगभग 12 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि गैर-फिल्टर खण्ड में 60 मि.मी. से कम की श्रेणी के लिए इस उद्योग

में तम्बाकू के अधिक उपयोग के लिए उत्पाद शुल्क कम करके 120 रुपए प्रति हजार से 60 रुपए प्रति हजार किया जा रहा है, जो परिणामतः तम्बाकू उत्पादकों को सहायता प्रदान करेगा।

87. पिछले कुछ वर्षों से जहां घरेलू अप्रत्यक्ष करों के आधार को व्यापक बनाने के प्रयास किए गए हैं, वहीं सेवा क्षेत्र को कराधान के अधीन नहीं लाया गया है। फिर भी, इस क्षेत्र का हमारे सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है और इसमें अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। कराधान से सेवाओं की छूट देने का कोई उचित कारण नहीं है, जबकि वस्तुओं पर कर लगता हो और कई देश कर प्रयोजनों के लिए वस्तुओं और सेवाओं दोनों को समान समझते हैं। कर सुधार समिति ने भी अप्रत्यक्ष करों के आधार को व्यापक बनाने के एक उपाय के रूप में सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की है। इसलिए मैं टेलीफोन की सेवाओं, गैर-जीवन बीमा और स्टॉक ब्रोकरों पर कर लगाकर इस दिशा में एक संतुलित प्रयास करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह कर टेलीफोन बिलों की राशि बीमा कंपनियों द्वारा प्रभारित निवल प्रीमियम और स्टॉक ब्रोकरों द्वारा उनकी सेवाओं के संबंध में प्रभारित दलाली अथवा कमीशन के 5 प्रतिशत की दर से प्रभारित होगा। ये प्रस्ताव बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से लागू होंगे।

88. उत्पाद शुल्क प्रभारित करने के लिए सामग्रियों के मूल्य के निर्धारण की मौजूदा प्रणाली बोझिल और समय लेने वाली है। इसमें निर्धारित द्वारा अग्रिम तौर पर मूल्य सूची दाखिल करना और उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा उनका अनुमोदन शामिल होता है। इस प्रक्रिया का पालन तब तक करना होता है जब भी मूल्यों में कोई परिवर्तन होता है। प्रक्रियागत सरलीकरण के एक उपाय के रूप में मैंने मूल्य सूची की अपेक्षा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। निर्धारित को अब बीजक में घोषित मूल्य के आधार पर उत्पाद शुल्क अदा करने की अनुमति दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि इस सुविधा का उद्योग द्वारा व्यापक स्वागत किया जाएगा। यह अंततः एक मूल्यवर्धित कर, जो बीजक के आधार पर मूल्य पर निर्भर करता है, को अपनाने का आधार बनाने में भी सहायक होगा।

89. घोषित उपायों के राजस्व निहितार्थों का विवरण वित्त विधेयक के व्याख्यात्मक जापन में दिया गया है।

90. मैंने सीमाशुल्क अधिनियम और उत्पाद तथा सीमाशुल्क में परिवर्तन करने के लिए वित्त विधेयक में कुछ अन्य संशोधनों का भी प्रस्ताव किया है। ये संशोधन मात्र समर्थकारी उपबंध हैं और इनमें महत्वपूर्ण राजस्व निहितार्थ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मौजूदा अधिसूचनाओं के संशोधन के प्रस्ताव हैं। सदन का समय बचाने के लिए मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता।

91. सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्कों में उपरोक्त परिवर्तन लागू करने वालों अधिसूचनाओं की प्रतिलिपियाँ यथा समय सदन के पटल पर रख दी जाएंगी।

92. अब मैं वर्ष 1994-95 के लिए अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों पर आता हूँ।

93. मैं उस मूल दर्जन को आगे ले जाने का प्रस्ताव करता हूँ जिसने वारों की संतुलित दरों और बेहतर कर प्रशासन के साथ आधार को व्यापक बनाने पर अधिक निर्भरता की एक साधारण प्रणाली का अनुसरण करने के लिए हमारे कर सुधारों को निर्देशित किया है।

94. मुझे कामगारों, मजदूर संघों और मध्यम श्रेणी के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निकायों से आयकर की छूट सीमा जो अभी तक 30,000 रुपये है, बढ़ाने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मुझे यह कहा गया है कि माँग उचित है और मैं यह छूट सीमा 35,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे 50,000 रुपये तक सकल आय वाला बेतनभोगी अथवा मजदूरी अर्जक कोई आयकर अदा नहीं करेगा। 52,000 रुपये तक का बेतन अर्जित करने वाली कामकाजी महिला भी कोई कर अदा नहीं करेगी।

95. मैं कर श्रेणियाँ जिनमें दो वर्षों से परिवर्तन नहीं किया गया है को समायोजित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इस समय, पहली श्रेणी जिस पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगता है 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक है। इसके बाद पहली श्रेणी 35,000 रुपये से 60,000 रुपये तक होगी जिस पर 20 प्रतिशत की समान दर से कर लगेगा। इस समय दूसरी श्रेणी 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक है, जिस पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगता है। इसके बाद दूसरी श्रेणी 60,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक होगी, जिस पर 30 प्रतिशत की उसी दर से कर लगेगा। 40 प्रतिशत की अधिकतम कर दर, जो अभी तक 1,00,000 रुपये से अधिक आय पर लागू होती है, अब से 1,20,000 रुपये से अधिक की आय पर लागू होगी।

96. मैंने पिछले वर्ष कहा था कि गैर-निगमित आय पर 12 प्रतिशत का अधिभार और एक वर्ष के लिए जारी रखने के लिए वाध्य था। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष है कि मैं अब पूरे अधिभार को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ।

97. पिछले वर्ष मैंने यह इंगित किया था कि निगमित कर ढाँचे में बड़े सुधार किए जाने वांछनीय हैं, फिर भी उन्हें एक वर्ष तक आस्थिर रखना होगा। मैं अब इन सुधारों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो हमारी सरकारी तथा निजी दोनों कंपनियों को अधिक बचत करने, अधिक निवेश करने और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता करेगा।

98. इस समय बहुजन धारित कंपनियों पर 45 प्रतिशत कर लगता है, जबकि अन्य घरेलू कंपनियों पर 50 प्रतिशत कर लगता है। मैं इस भेद को जो अब भी बहुजन धारित और अल्पजन धारित घरेलू कंपनियों की कर दरों के बीच मौजूद है को हटा देने और दोनों दरों को कम करके 40 प्रतिशत की एकल दर पर करने का प्रस्ताव करता हूँ।

99. 75,000 रुपये से अधिक आय वाली सभी घरेलू कंपनियों को 15 प्रतिशत की दर पर अधिभार अदा करना होता है। हालाँकि, मैं इस अधिभार को समाप्त करने का इच्छुक हूँ, लेकिन राजस्व संबंधी बाधाएं मुझे अभी इस लेवी को जारी रखने के लिए मजबूर कर रही हैं। विदेश में निगमित, परन्तु भारत में आय अर्जित करने वाली कंपनियों पर इस समय 65 प्रतिशत का कर लगता है। निगमित कर दरों में सामान्य कमी के अनुरूप, इस दर को भी कम करके 55 प्रतिशत किया जा रहा है।

100. हमारी आर्थिक नीतियों के परिणामों में से एक भारतीय कंपनियों को बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धी स्थिति सुधारने के लिए पुनः संरचित करने की आवश्यकता है। इसके लिए व्यापारिक आस्तियों के हिस्से से वंचित करने अथवा निष्क्रिय आस्तियों से संभावित मूल्य की वसूली करने की जरूरत हो सकती है, जिसमें से दोनों के लिए दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभ कर आवश्यक होंगे। यह पुनर्संरचना के निवारक के रूप में कार्य करता है। घरेलू कंपनियों पर ऐसे दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभ कर की मौजूदा दर 40 प्रतिशत है, जबकि व्यक्ति विशेषों के दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर केवल 20 प्रतिशत कर लगता है। इसलिए, मैं घरेलू कंपनियों पर पूंजी अभिलाभ कर की दर कम करके 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

101. मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि शेयरों के समान, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और अन्य अनुमोदित म्यूचुअल फंडों की यूनिटें, अगर उन्हें 12 महीने से अधिक अवधि के लिए धारित किया जाता है, को भी परिणामी लाभों सहित दीर्घावधिक पूंजीगत आस्तियाँ माना जाएगा; ऐसी यूनिटों के लिए अर्पणित धारिता अवधि अभी 36 महीने है। इससे यूनिटों में निवेश करने वालों, जो सामान्यतया निम्न मध्यम अथवा मध्यम वर्ग के होते हैं, को पर्याप्त राहत प्राप्त होगी।

102. अनिवासियों की निवेश आय (अर्थात् लाभांश और ब्याज आय) के कराधान की दरें प्राप्तकर्ता की कर हैसियत के साथ परिवर्तनीय होती हैं। मैं सभी अनिवासी कंपनियों और अनिवासी व्यक्तियों (चाहे वे भारतीय हों अथवा विदेशी) को होने वाली ऐसी आय पर 20 प्रतिशत की एक समान दर द्वारा ऐसे कराधान की योजना को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ।

103. अनिवासी भारतीयों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यदि वे भारत की यात्रा करें और 149 दिवस से अधिक

ठहरें तो उसका प्रतिवासी का दर्जा समाप्त नहीं होगा चाहिए। मैं इस प्रयत्न को 181 दिवस करने का प्रस्ताव करता हूँ।

104. दो वर्ष पहले मैंने वृद्ध जनों (अर्थात् जिनकी आयु 65 वर्ष और उससे अधिक है) के लिए देय कर के 10 प्रतिशत की विशेष कर राहत आरंभ की थी, यदि उनकी आय 50,000 रुपये से कम है। पिछले वर्ष मैंने कर छूट को बढ़ाकर 20 प्रतिशत और आय सीमा को भी बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया था। अब मैं उनके लिए स्वीकार्य छूट को देय कर के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत और यह लाभ एक लाख रुपये तक की आय वाले वृद्ध जनों के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ।

105. वर्ष 1992 में, हमने किसी शिशु की आय को उसके माता-पिता की आय के साथ मिलाने का निर्णय लिया था। इससे विकलांग शिशुओं और उनके माता-पिता से संबंधित मामलों में अनावश्यक कठिनाइयाँ बढ़ी हैं। यदि किसी शारीरिक रूप से विकलांग शिशु की कर-पञ्च आय किसी तरह कम नहीं हुई है, तो मैं ऐसे विकलांग शिशुओं की आय को आयकर और धनकर अधिनियमों, दोनों के अंतर्गत मिलाने के प्रावधानों से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

106. स्व-रोजगार वाले लोगों द्वारा उनके बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से एक पेंशन निधि में अंशदान करने के लिए, भारतीय यूनिट ट्रस्ट एक निधि स्थापित करने जा रहा है। मैं ऐसी किसी पेंशन निधि में किए जाने वाले अंशदान की आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूट के लिए पात्र शर्तों में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ।

107. मातृत्व संरक्षणों के विकास में निवेश विकास और प्रगति के लिए एक अतिव्यापक पुनर्निर्माण है। अनेक विद्यार्थी अध्ययन के लिए श्रम लेते हैं। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों, जो विविध संस्थाओं से छात्रा शिक्षा के लिए श्रम लेते हैं, की सहायता करने के उद्देश्य के रूप में मैं आय से मुक्तपत्र की वापसी प्रदायगियों और ब्याज की प्रदायगियों के रूप में 2 लाख रुपये तक की कुल संवित राशि पर 25,000 रुपये प्रतिवर्ष की आय पर कटौती देने का प्रस्ताव करता हूँ। यह कर रियायत उन विद्यार्थियों को उपलब्ध होगी, जो इंजीनियरी, चिकित्सा अथवा प्रबंधन में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर या शिक्षा, अनुप्रयुक्त विज्ञान, गणित अथवा सांख्यिकी में स्नातकोत्तर अध्ययन करते हैं।

108. विकास के संवर्धन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। इस समय, जब कोई निर्धारित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला को अंशदान देता है, उसे अंशदान के 125 प्रतिशत की भारित

कटौती प्राप्त होती है। मैं यह लाभ सभी विश्वविद्यालयों, सम-विश्वविद्यालयों, भारतीय औद्योगिक संस्थानों, तथा अनुसंधान और शिक्षा संस्थान, कर्लवट्रानिक विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग और प्राणविक सर्जरी विभाग के तत्वाधान में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

109. कुछ विश्वविद्यालयों और सहकारी समितियों ने मायावेदन दिए हैं कि अनुसूचित स्वीच्छक गैरनिर्वाचित गोनलाओं से संबंधित धारा 10 (10ग) के अंतर्गत कर छूट उनके कर्मचारियों को भी प्रदान की जानी चाहिए। मैं उनके अभ्यावेदनों को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ।

110. पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्थापित सरकारी निगमों की आय को छूट देने संबंधी सरकार के विचार को दर्शाने वाला एक वस्तुस्थिति संवाद के पिछले सत्र में पहले ही दिया जा चुका है। मैं इस व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए विधायी संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

111. सम्पत्ति की हिस्सेदारी (कम्प्यूनीओ डोस वेन्स) की प्रणाली गोवा, दमण, दीव, दादरा और नागर हवेली के निवासियों के लिए विशेष महत्व की है। हाल ही में कुछ व्यापिक निर्णय लिए गए हैं, जिनके अनुसार किसी भी गोवानी परिवार की व्यावसायिक आय पूर्णतया एक व्यक्ति के हाथ में होने से कर योग्य हो जाती है। इन निर्णयों ने ऐसी आय के पति तथा पत्नी के बीच बराबर विभाजन और दोनों के मामले में अलग-अलग कर-निर्धारण की चिर-सम्भावित प्रणाली को प्रभावित किया है। मैं सज्जता हूँ कि इससे गोवानी दम्पतियों के बीच अनावश्यक तनाव और किन्ता पैदा हुई है। इस क्षेत्र में सभी विवादों को समाप्त करने के लिए मैं आयकर अधिनियम में उचित संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ, ताकि गोवा में सम्पत्ति की हिस्सेदारी की प्रणाली द्वारा शासित नागरिकों के वेतनों को छोड़कर, कोई भी अन्य आय पति तथा पत्नी के बीच बराबर विभाजित की जाएगी और कर-निर्धारण अलग-अलग किया जाएगा।

112. पिछले कुछ वर्षों में हमने कर्मचारियों के मामले में चिकित्सा व्यय के रूप में अनुलाभों के कराधान को उदार बनाया है। मैं कर्मचारियों द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों को प्रगत बिलों की प्रतिलिपि को शामिल करके लाभों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

113. जो लोग अपने घरानों में रहते हैं, उन्हें राहत देने और गृह निर्माण को एक प्रोत्साहन के रूप में मैं गृह निर्माण के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज के कारण कटौती का आयकर के प्रयोजनों के लिए 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

114. हम पिछले दो वर्षों से असंगठित क्षेत्र में निर्यातियों के कराधान की एक सरल आनुमानिक स्कीम कार्यान्वित करते रहे हैं। यह स्कीम इस वर्ष समाप्त हो जानी थी। मैं इस स्कीम को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे आशा है कि आधिकारिक लोग इस स्कीम से लाभ उठाएंगे और बिना किसी भय अथवा बाधा के राष्ट्रीय कर प्रयास के लिए अपनी क्षमतानुसार योगदान देने के लिए तत्काल आगे आएंगे।

115. इसके अतिरिक्त उन ठेकेदारों, जिनका व्यापार 40 लाख रुपए तक का है और उन ट्रक-मालिकों, जिनके पास ट्रकों की संख्या दस तक है, के लिए एक नई आनुमानिक आय योजना आरम्भ कर रहा हूँ। ठेकेदारों के मामले में निवल लाभ का अनुमान सकल प्राप्तियों के 8 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। ट्रक मालिकों के मामले में, आय का अनुमान हल्के वाणिज्यिक वाहनों और मध्यम मोटर वाहनों के लिए 24,000 रुपए प्रति ट्रक प्रति वर्ष तथा भारी माल वाहक मोटर वाहनों के लिए 30,000 रुपए प्रति ट्रक प्रति वर्ष की दर से लगाया जाएगा। इन दोनों के ही मामले में, मूल्यह्रास अथवा ब्याज अथवा किसी अन्य व्यय के कारण किसी अतिरिक्त कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों ही मामलों में यह योजना वैकल्पिक है। यह योजना कर सुधार संबंधी चेलैय्या समिति समिति की सिफारिशों पर आधारित है। यह योजना बिल्कुल सरल और झमेलों से मुक्त होगी तथा मुझे आशा है कि इस योजना का उत्साहपूर्ण स्वागत किया जाएगा।

116. पिछले वर्ष मैंने आयकर अधिनियम की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट राज्यों में उत्पादन शुरू करने वाले नये औद्योगिक उपक्रमों के लिए पांच वर्ष के करावकाश की घोषणा की थी। सब तरफ से बार-बार यह मांग दोहराई जाती रही है कि यह लाभ अन्य राज्यों के पिछड़े हुए जिलों में भी जारी किया जाना चाहिए। मैंने घोषणा की थी कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया जाएगा। इस दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा इस पर विचार किया जा रहा है। देश के अन्य राज्यों के पिछड़े जिलों में नये निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए मेरा ऐसे जिलों को यह रियायत देने का प्रस्ताव है, जो कतिपय निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार पिछड़े हुए हैं।

117. आयकर अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल की गई मंदों के निर्माण में जुटे नए औद्योगिक उपक्रमों की बड़ी इकाइयों को भी लाभ में कटौती की अनुमति प्रदान करने के संबंध में सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है, बशर्ते कि ऐसे एककों की स्थापना आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट पिछड़े राज्यों में की जाए। मैं इस उद्देश्य को वैधानिक रूप देने का प्रस्ताव करता हूँ।

118. कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात को प्रोत्साहन देना जारी रखने की दृष्टि से, मैं ऐसे निर्यात संबंधी लाभों पर छूट को और एक वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

119. अपने देश में पर्यटकों को आकर्षित करने का हमारा एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम है। इस बात पर जोरदार बल दिया जाता रहा है कि होटलों में किए गए व्यय पर मौजूदा कर की दर से पर्यटन हतोत्साहित होता है। इसलिए, मैं इस व्यय को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। ऐसा कदम मैं इस आशा के साथ उठा रहा हूँ कि राज्य सरकारें भी इसका अनुसरण करेंगी और होटलों में अपने कराधान को कम करेंगी, जिससे देश के भीतर पर्यटन को बढ़ावा मिले तथा अधिक विदेशी पर्यटक यहां आएँ।

120. प्रदूषण पर नियंत्रण रखना हम सब के लिए अत्यधिक महत्व की बात है। इसलिए, मैं आयकर अधिनियम की धारा 35क के अंतर्गत रियायत के लिए पात्र परियोजनाओं में प्रदूषण नियंत्रण को भी शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की परियोजना में अंशदान करता है, वह कर कटौती के रूप में ऐसे शत-प्रतिशत अंशदान का दावा कर सके।

121. विवाह के अवसर पर दान कर की छूट सीमा 30,000 रुपए तथा उपहार देने आदि के संबंध में दान कर हेतु 30,000 रुपए की अतिरिक्त छूट उपलब्ध है। विवाह जैसे खुशी के अवसर पर सभी परिवार एकत्र होते हैं तथा जहां तक संभव हो ऐसे शुभ अवसरों पर ईमानदार कर-दाता नागरिकों को कर से मुक्त रहने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए, मैं आश्रित रिश्तेदार के विवाह के अवसर पर ऐसे उपहारों हेतु छूट की सीमा 30,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

122. परम्परागत अनुमान के अनुसार, सीमात्मक में प्रस्तावित परिवर्तनों से 2,981 करोड़ रुपए की राजस्व हानि तथा 699 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा। उत्पाद शुल्क पक्ष में 2,106 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होने तथा राहत राशि 2,000 करोड़ रुपए होने का पूर्वानुमान है। प्रत्यक्ष करों में परिवर्तनों से व्यक्तिगत आयकर संग्रहण में 1,075 करोड़ रुपए तथा निगमित कर में 1,355 करोड़ रुपए की हानि होगी। व्यय कर में 75 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है। सेवा संबंधी करों से होने वाले 600 करोड़ रुपए के लाभ को हिसाब में लेने के पश्चात्, परिकलन के पारम्परिक तरीकों से लगाए गए अनुमान के अनुसार कर संबंधी निवल हानि 4,081 करोड़ रुपए बँटती है। व्यक्तिगत आय कर में राहत देने के कारण राज्यों को 625 करोड़ रुपए की हानि होगी तथा उत्पाद शुल्क में 148 करोड़ रुपए का लाभ होगा। इन परिकलनों के आधार पर केन्द्र को 3,604 करोड़ रुपए की हानि होगी।

123. सामान्यतया, ऐसे समय जब राज कोषीय प्रणाली दबाव में हैं, इतनी मात्रा की राजस्व क्षति को अतिरिक्त कर लगाने अथवा मौजूदा दरों में वृद्धि करने की अपेक्षा होगी। मैंने यह कार्रवाई कई कारणों से नहीं की है। राजस्व हानि का परिकलन कर ढांचे के सरलीकरण और योक्तिकीकरण, जो राजस्व संग्रहण में सहायता करेगा, को कोई श्रेय नहीं देता। राजकोषीय विशेषज्ञ लगभग एकमत हैं कि हमारी प्रणाली में करों का काफी अपवंचन होता है और कर दरों को कम करना और फिर भी कर प्रशासन और अनुपालन को सुधार कर अतिरिक्त राजस्व जुटाना संभव है। अभी लागू किए जा रहे प्रत्यक्ष कर ढांचे में सरलीकरण विवेक, विवाद और मुकदमेबाजी की संभावना को कम करेगा, जो कभी कर अपवंचन के एक स्रोत हैं। मूल्यानुसार उत्पाद शुल्कों की और अंतरण भी उत्प्लावकता में वृद्धि करेगा। मैं कर प्रशासन सुधारने के लिए एक बड़े प्रयास करने का प्रस्ताव करता हूँ। कर कानूनों का प्रशासन सही तरीके और दृढ़ता से किया जाने वाला है। कम्प्यूटरीकरण, जो दोनों विभागों में शुरू हो चुका है, से कर प्रशासन में और सुधार आने की आशा है। मुझे यह भी आशा है कि करदाता, जिन्होंने लंबे समय से कर की दरों को नियंत्रित करने की मांग की है, अब प्रशासन दिया है कि इससे अनुपालन में सुधार होगा, अब अपने इस समझौते पर कायम रहेंगे। अंततः इस प्रयोग की सफलता से उन्हें ही अधिक लाभ होगा।

124. हर जगह आर्थिक जीवन की विशेषता अत्यंत अनिश्चितता है। हमेशा यह संभावना रहती है कि शायद सभी बातें वैसी नहीं हो सकती, जैसी मैंने प्रत्याशा की हैं। यद्यपि, कोई भी इन मामलों में सिद्धांतवादी नहीं हो सकता फिर भी मेरा पक्का विचार है कि मेरे द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई में शामिल जोखिम विवेक की सीमा पार नहीं करेंगे। कर सुधार को स्थगित करने अथवा पारम्परिक रूप से यथा परिकलित राजस्व हानि को प्रतिसंतुलि करने के लिए अतिरिक्त कर अधिरोपित करना, ऐसी स्थिति में पूर्णतः अनुत्पादक होगा, जहाँ हमारी अर्थव्यवस्था की विशिष्टता पर्याप्त अप्रयुक्त औद्योगिक क्षमता, रिकार्ड खाद्य भंडारों और पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों से परिलक्षित होती है। ऐसी कोई भी कार्रवाई उस आर्थिक पुनरुत्थान, जिसकी हमारे देश को आवश्यकता है और जो अभी हमारे सामने है, को धक्का पहुंचा सकती है।

125. इन कारणों से, मैं बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप किसी राजस्व हानि के अनुमान लगाने का प्रस्ताव नहीं करता हूँ। इसलिए, बजट घाटा 6,000 करोड़ रुपए तथा राजकोषीय घाटा 54.915 करोड़ रुपए पर ही रहेगा। इस स्तर पर, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के आसपास रहेगा। यह मेरी आशा से अधिक है, परंतु जैसा कि मैंने कहा है कभी कर सुधारों में कुछ जोखिम बने रहते हैं।

126. यह बजट अर्थव्यवस्था के लिए संकटग्रस्त समय पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इतिहास में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो निर्णायक कार्यवाई की मांग करते हैं। कार्रवाई न करने अथवा अच्छा प्रत्युत्तर न देने के भयंकर परिणाम निकल सकते हैं, जिन्हें सदियों तक महसूस किया जाता है। जून, 1991 का समय एक ऐसा ही मौका था। हम प्रधान मंत्री, श्री पी. वी. नरसिम्हा राव द्वारा प्रदान किए गए शानदार नेतृत्व के आभारी हैं, जिससे हम अपने भाग्य की प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलने में सफल रहे। तथापि, किसी भी तरह राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य समाप्त नहीं हुआ है। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें हमें दशक की शेष अवधि में संलग्न रहना चाहिए। परंतु, हम आज इस कार्य को एक सुदृढ़ स्थिति में कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बना दिया गया है और यह आने वाले वर्षों में तीव्र वृद्धि की क्षमता प्रदर्शित करती है, हमारा कृषि क्षेत्र, नई नीतियों का प्रत्युत्तर देने के लिए सुदृढ़ और सुव्यवस्थित है। हमारे निजी और सरकारी, दोनों औद्योगिक क्षेत्रों ने बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धी बाजार स्थितियों का सामना करने के लिए पुनर्संरचना का कठिन कार्य प्रारंभ कर दिया है। देशी और विदेशी दोनों निवेशों के वातावरण में बहुत सुधार हो गया है। अब प्रस्तावित कर ढांचा आधुनिक कर प्रणाली और संतुलित कर दरों की ओर अग्रसर है तथा अनुपालन पर बल देता है, जो सभी सफल देशों के प्रमाण चिह्न हैं। मुझे विश्वास है कि यह नए निवेशों आर्थिक पुनरुत्थान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता, जिसकी आज अर्थव्यवस्था को आवश्यकता है, के लिए मजबूत प्रेरणा प्रदान करेगा। कर सुधार समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित मध्यावधिक उद्देश्य अब स्पष्ट रूप से हमारी पहुंच के भीतर है।

127. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट एक दृढ़ विश्वास से प्रेरित है कि भारत के पास विश्व का अग्रिम पंक्ति वाला राष्ट्र बनने के लिए सभी भौतिक और मानव संसाधन उपलब्ध हैं। हम एक नई सदी, निस्संदेह एक नए स्वर्ण युग के कगार पर हैं। कई विस्मयकारी अवसर मौजूद हैं, बशर्ते कि हमारे पास उनका लाभ उठाने की दूरदृष्टि और विवेक हो। अगर हम हिम्मत हार गए या निर्णय लेने में डांवाडोल हो गए तो इसके कई भयानक खतरे भी हैं। महोदय, यह तब आदर्शवाद के उन महान सिद्धान्तों के लिए परिश्रम करने का समय है, जिसने भारत के चमकते भाल को उस पर धब्बा लगाए और धुंधला किए बिना हमारी आजादी की लड़ाई को और मजबूत दरादों को दृढ़ रहने की प्रेरणा दी है, जैसे जवाहरलाल नेहरू कहना पसंद करते थे कि यह अपनी महान और अनंत युग चेतना को मूर्त रूप देता है, ताकि इसका प्रकाश घर-घर में पहुंचे और आशा, विश्वास तथा साहस प्रज्ज्वलित करे और भारतीय होने में गर्व महसूस कराए। आइए, हम अनथक प्रयास करें, जैसा कि महान कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए अपनी प्रार्थना में कहा था, जहाँ "विवेक का निर्मल सरित प्रवाह निर्जीव आदतों की शुष्क मरुभूमि में अपना रास्ता न भूल

जाएँ। आइये, हम इस महान कार्य और भारत की इस प्राचीन और पवित्र भूमि के योग्य बनें।

128. महोदय, मैं यह बजट इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

एन. पी. बागची, अपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

(Budget Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1994

F. No. 15(38)-B(D)93 :—The following is published for general information :—

BUDGET 1994-95

Speech of Shri Manmohan Singh, Minister of Finance.

28th February, 1994

PART A

Sir,

It is with a sense of great privilege, and also deep humility, that I rise to present the Budget for 1994-95.

2. Less than three years have passed since our Party, under the inspiring leadership of Prime Minister Shri P. V. Narasimha Rao, came into office, as a minority Government at that time, facing the awesome task of rebuilding a shattered economy. The Prime Minister had pledged that we would give top priority to grappling with the grave economic crisis and put the economy back on a path of strong sustainable growth. In pursuit of this mandate we embarked on a far reaching programme of economic restructuring and reform.

3. Three years are not enough to complete economic restructuring in a country as complex as India, but it is time enough to take stock. I am sure all Honourable Members will agree that the economic situation has shown substantial improvement. Progress on the external front has been dramatic.

Our foreign currency reserves, which were a little over \$1 billion in June, 1991 are now close to \$13 billion. Our gold, which earlier had been pledged abroad, is back in our possession.

Exporters are responding very well to our sweeping reforms of exchange rate and trade policies. Our exports have increased by a remarkable 21 per cent in dollar terms in the first 10 months of 1993-94. This compares, for the corresponding period, with a decline of 3 per cent in 1991-92 and a rise of 2 per cent in 1992-93.

Despite all the fears that liberalisation would lead to a flood of imports, the dollar value of our imports during April-January 1993-94 was less than one per cent higher than imports during the corresponding period of 1992-93. For the fiscal year 1993-94 imports are likely to be lower than even 1990-91.

The current account deficit in our balance of payments during 1993-94 will be less than half a per cent of GDP compared to over 3 per cent in 1990-91 and 2 per cent in 1992-93.

Contrary to what many feared, the exchange rate for the rupee has remained remarkably steady despite unification and lifting of trade controls. Foreign exchange is flowing through legal channels in ample quantities instead of through hawala transactions as earlier.

* International confidence in India has been restored. Foreign direct and portfolio investment, which was hardly \$150 million in 1991-92, is likely to be around \$3 billion in 1993-94.

4. The news on the domestic economy is also encouraging. Inflation has been reduced from the peak of 17 per cent in August 1991 to about half that level at present. Agricultural performance has been strong. Food stocks in the public system stood at over 23 million tonnes on 1st January, 1994. This is the highest level in seven years and provides invaluable insurance against any possible crop failure. Industrial growth is also recovering, though more slowly than we had hoped. Overall economic growth is estimated at about 4 per cent for the second year in a row. Fears that the reform programme might lead to a large scale increase in unemployment have turned out to be unfounded. The latest available data of persons registered with employment exchanges and seeking jobs show a fall of 1.4 per cent in November 1993 as compared to November 1992.

5. The slow growth of industry in 1993-94 is a matter of concern and is largely due to the sluggishness of the capital goods sector. If capital goods are excluded, the rest of the manufacturing sector shows 6 per cent growth in the second quarter and is expected to improve in the rest of the year. The recession in the capital goods industries is primarily because investment activity slowed down temporarily as firms adjusted their investment plans to the new situation. There are signs that this restructuring process is well advanced and many companies are now launching major programmes to enhance their international competitiveness. The turnaround in investment is, therefore, beginning.

6. In real life the picture is never entirely rosy and there are some warning signals which we must heed. It has not been possible to contain the fiscal deficit in the current year to the level we had originally targeted. The slower pace of industrial recovery in 1993-94 led to a shortfall in revenues and various expenditures have also exceeded Budget esti-

mates. The slippage in the fiscal deficit in 1993-94 has been less damaging than might have been the case ordinarily, mainly because of the existence of sizeable idle industrial capacity and low investment levels. But as investment begins to revive, we cannot afford continuing weakness on the fiscal front. Unless the deterioration witnessed in the current year is speedily reversed, there is a serious danger that we may slip back into a position where large government deficits fuel inflation, widen the current account imbalance and push up interest rates, making it impossible to bring about the rapid economic growth we need to raise living standards and create productive jobs in adequate numbers.

7. In formulating this Budget, I have sought to address six major tasks :

- First, we must accelerate the reform and modernisation of our tax system we began two years ago.
- Second, we must correct the slippage in the fiscal deficit that has occurred in the year.
- Third, we must build on the demonstrable success already achieved in the external sector where our strong performance has vindicated our strategy of phased integration with the world economy.
- Fourth, the Budget must provide a major stimulus for a strong industrial recovery, especially for investment and capital goods production.
- Fifth, and most importantly, we must re-orient our development policies and programmes to address more effectively the problems of poverty, unemployment and social deprivation which affect a large mass of our people, particularly in rural areas.
- Sixth, we have to consolidate and deepen the progress we have made in restoring the health of our banking system.

8. Last year we moved to a unified, market-determined exchange rate system. The system has worked extremely well. The time has come to take the next step and move towards convertibility on the current account. Current account convertibility will substantially liberalise the access to foreign exchange for all current business transactions and also liberalise foreign exchange access for travel, education and medical expenses, etc. This will virtually eliminate reliance upon illegal channels for such transactions. The details of these liberalisations are being separately announced by the Reserve Bank. Consistent with the progressive liberalisation of our external payments regime, we shall review the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, and undertake necessary changes, including if necessary, its replacement by new legislation.

9. Our policies towards foreign direct and portfolio investment have yielded good results and have helped us reduce our reliance on foreign borrowing.

Much of the direct investment approved has been for critical infrastructure sectors. As envisaged in my Budget speech last year, Government is currently negotiating bilateral investment treaties with several major investor countries.

10. Our external debt, which is a cause of concern, is growing more slowly now. It grew by about \$6 billion per year on an average in the latter half of the 1980s. In 1990-91 the debt grew by over \$8 billion. In 1991-92 and 1992-93, the increase averaged only about \$3 billion. In the first half of 1993-94 external debt has increased by hardly \$300 million. Furthermore, the recent increase in debt has been more than offset by the sharp increase in our foreign currency reserves. I would like to assure the House that we shall remain vigilant on this front so that external debt remains within prudent levels. There is no question of India falling into a debt trap. In fact, we propose to respond to the easier payments position by retiring some of the high cost debt we have incurred in the past. Indian companies will be freely permitted to pre-pay past foreign loans.

11. Honourable Members are aware that some of our external debt is owned to the IMF. We had approached the Fund in our hour of difficulty. Now that our payments situation has improved considerably and our reserves have been rebuilt to comfortable levels, we are in a position to repay the Fund somewhat ahead of schedule. Repayments of principal and interest amounting to \$1.4 billion are due to the Fund in 1994-95. Instead of following the regular schedule of payments we intend to pre-pay entire amount at the beginning of the year. This decision to prepay in no sense detracts from the excellent relations we have with the Fund which has helped us immensely in our time of need. We will not hesitate to seek financial support again, if conditions warrant.

12. At present exporters and other foreign exchange earners, are permitted to retain up to 15 per cent of foreign exchange receipts in an account designated in foreign currency. It has been decided to increase the percentage of retention allowed from 15 to 25 per cent. As a special incentive, for 100% Export Oriented Units and units in Export Processing Zones as well as units in Electronic Hardware Technology Parks and Software Technology Parks, the retention allowed will be 50 per cent. This facility is designed to protect exporters from having to incur conversion costs when they make payments for imports. The necessary notifications are being separately issued by the Reserve Bank of India.

13. Turning to the need to strengthen fiscal discipline, I have long felt that Government should not be able to finance its deficits by creating money, through unlimited recourse to the Reserve Bank, by issue of ad hoc Treasury Bills. This practice has also weakened the Reserve Bank's capacity to conduct effective monetary policy. As a corrective measure, I propose to phase out the Government's access to ad hoc Treasury Bills over a period of three years. In 1994-95 the budget deficit is being limited to about two-thirds of one per cent of expected GDP, or Rs. 6,000 crore. Normally, net issue of ad hoc

Treasury Bills for the year as a whole should not exceed this amount. It has also been agreed with the Reserve Bank that the net issue of ad hoc Treasury Bills should not exceed Rs. 9,000 crore for more than ten continuous working days at any time during the year. If this happens, the Reserve Bank will automatically sell Treasury Bills in the market to reduce the level of ad hoc Treasury Bills. This is a historic step which will in due course contribute to a significant improvement in fiscal and monetary discipline, and give the Reserve Bank greater scope for effective monetary management. In subsequent years, the recourse to ad hoc Treasury Bills will be progressively reduced and by 1997-98, the Government will cease to have direct recourse to the Reserve Bank for financing its deficit and will have to meet its entire requirements through borrowing from the market.

14. Interest rates have an important influence on investment in industry and other sectors of the economy. There have been repeated demands that interest rates should be brought down. The minimum lending rates charged by banks have been brought down already by three percentage points over the past year. The Financial Institutions have also reduced their effective rates. I am happy to inform the House that the All-India Financial Institutions are now reducing their minimum lending rate by a further one percentage point to 14 per cent exclusive of interest tax. Simultaneously, the commercial banks' minimum lending rate on term loans of three years and above is also being reduced from 15% to 14%. The Reserve Bank is separately issuing the notification. These changes take effect from tomorrow and will help to stimulate investment in the economy.

15. Government had earlier proposed certain amendments to the Companies Act to streamline the Act in line with the contemporary requirements. Several representations have been received from industry seeking modifications of these proposals to give Indian companies an environment in which they can compete effectively in the highly competitive market place. Government has reconsidered the matter in the light of these representations and it is proposed to submit a new Bill to Parliament which will be responsive to these concerns.

16. We live in a world where science and technology have become a major determinant of the power and wealth of nations. India is proud of the achievements of its sciences and technologies, but a great deal more needs to be done to make science and technology an effective instruments of nation renewal. To accelerate the development and application of indigenous technology to production processes, I propose to credit the 5 per cent cess on payments of royalty for imported technologies which is presently collected under the Research and Development Cess Act, 1986, into a new Fund for Technology Development and Application. This Fund will be placed at the disposal of the Department of Science and Technology to help the indigenously developed technologies reach the stage of commercial application. Necessary amendments to this effect will be made in the R&D Cess Act. I shall propose some further measures to promote research and development when I come to my tax proposals.

17. I would like to assure the House that our policies are geared towards promoting a dynamic and internationally competitive industrial sector. I am confident that given our vast reservoir of skilled manpower and entrepreneurship, Indian industry has the capacity and the will to meet the challenge of global competition. Government and industry will work as active partners to usher in the second industrial revolution which is both more efficient and more employment-oriented. This year, my revenue proposals, to which I will come later, include a strong package of measures to boost industrial investment and capital goods production. Looking ahead, I have a vision of our industrial firms acquiring a global reach and their names becoming household words in far off, distant lands.

18. Let me now turn to some issues relating to agriculture. An adequate flow of institutional rural credit to agriculture is vital for the development of the rural sector and this flow at present is unduly low in relation to need. The reasons include high costs of intermediation incurred by banks and cooperatives, fundamental weaknesses in the institutional structure and unsustainable restrictions on credit and interest rate policy. I propose to take a number of significant steps to lay the basis for a long-term improvement in rural credit. The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) is the apex agency for rural credit. I am providing Rs. 100 crore for augmenting its share capital and the Reserve Bank will contribute an equivalent amount. This will nearly triple NABARD's share capital and equip it to play a strong leadership role in strengthening the system of rural credit.

19. One of our major concerns in rural credit has been the weak condition of the Regional Rural Banks (RRBs). Of the 196 regional rural banks, as many as 150 have shown losses in each of the past five years. Many have completely wiped out their equity and reserves and in some the losses are eating into deposits. This is an unsustainable situation and long-term structural measures are necessary if these banks are to be rehabilitated. The Reserve Bank has already announced some measures giving RRBs greater flexibility in their lending operations to make them more viable. I propose to take up 50 of the 196 RRBs from all over the country in the course of 1994-95 for undertaking comprehensive restructuring, including cleaning up of their balance sheets and infusion of fresh capital. The form and modality of the restructuring and associated financial support will be worked out during the year. The experience with these 50 RRBs will guide our approach in later years to the other RRBs. The success of this programme will depend on full cooperation from State Governments and sponsor banks, who are shareholders, as well as the employees of RRBs. Our objective is to transform presently weak and ailing RRBs into financially viable and effective instruments of decentralised rural banking.

20. In addition, we must find ways of strengthening the co-operative credit structure which has played a significant role in rural development through credit support. As against Rs. 6,295 crore of new lending by cooperatives during 1992-93, they are expected

to reach Rs. 8,500 crore during 1993-94. During 1994-95 we are planning for a further increase to Rs. 9,600 crore. This quantitative expansion must be accompanied by organisational and structural changes which ensure financial viability. The Government proposes to initiate a series of measures for strengthening the cooperative structure. NABARD will be entering into memoranda of understanding with State and District Cooperative Banks and concerned State Governments for implementing State-specific development action plans to revamp the cooperative system and improve its viability.

21. These measures to strengthen the rural credit system are being accompanied by a substantial increase in the budget provision for Rural Development to which I will come shortly. It will also be our objective to ensure that our policies towards agriculture eliminate all unnecessary restraints on farmers. Restrictions on domestic movement of foodgrains and other agricultural goods must be completely removed, so that our farmers can reap the benefits of an united national market. They must also be increasingly free to export, thus not only making their due contribution to our national export effort, but also benefiting from profitable export opportunities.

22. Honourable Members are aware, we have embarked on a basic restructuring of the banking system aimed at ensuring full financial viability of its operations and strengthening its competitive capability. I provided a sum of Rs. 5,700 crore as capital contribution to the nationalised banks in 1993-94 to help them make necessary provisions against bad and doubtful loans and meet the new capital adequacy norms. I had indicated last year that there would be additional capital needs in 1994-95 and 1995-96 and also that this burden could not be borne exclusively by the Budget. I am happy to report to the House that in December 1993 and January 1994, the State Bank of India successfully raised over Rs. 2,200 crore from the public through issue of equity and another Rs. 1,000 crore through a bond issue. To allow the nationalised banks to access capital markets in the same way, and mitigate the burden on the Budget, legislative amendments were introduced in the Lok Sabha in the Winter Session. Their speedy passage will help many of these banks to mobilise the capital they need to meet their requirements. Many nationalised banks will nevertheless require additional support during 1994-95 and I am providing Rs. 5,600 crore in 1994-95 as additional capital contribution for these banks. As before, this capital will be provided in the form of Government bonds on which there will be no immediate cash outgo. Interest payments and amortisation will of course be a charge on future budgets.

23. I am grateful to this House for quick passage last August of the Recovery of Debt due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 which provides for the establishment of Special Recovery Tribunals. These Tribunals will soon be operational, and will play a major role in improving the recovery of banks' dues. I am also happy to report that the Reserve

Bank is setting up the Board for Financial Supervision to supervise the banks and other financial institutions. To alert banks and financial institutions and put them on guard against borrowers who have defaulted in their dues to other lending institutions, the Reserve Bank of India is putting in place arrangements for circulating among banks and financial institutions. To alert banks and financial institutions a threshold limit. The Reserve Bank will also publish a list of defaulting borrowers in cases where suits have been filed by banks and financial institutions. Both these measures will encourage greater discipline among the borrowers.

24. The Government attaches high priority to forms of the capital markets aimed at creating an efficient and competitive capital market subject to effective regulation by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) which will ensure adequate investor protection. After a temporary setback in 1992 following the securities scam, the capital market recovered ground quickly. The funds mobilised in the capital market through public and rights issues, duly approved by SEBI, in the first ten months of 1993-94 were over Rs. 18,000 crore, as compared to less than Rs. 16,000 crore in the same period of 1992-93 and under Rs. 6,000 crore for the full year, 1991-92. In addition, a number of Indian companies raised funds abroad through Euro-equity issues and Foreign Currency Convertible Bond Issues. The Government is committed to a thorough modernisation of the capital market and rapid improvement of trading practices with a view to ensuring transparency and speed of settlements. The model National Stock Exchange with screen-based trading is expected to begin operation by the middle of this year. The establishment of a Depository System of scripless trading is another important objective. Government intends to bring before Parliament separate legislation for the establishment of Depositories. The Government also proposes to make further amendments to the SEBI Act and the Securities Contracts (Regulation) Act in order to give additional powers to SEBI.

25. In my Budget speech last year, I had announced the establishment of a High-Powered Committee to study the insurance industry and make recommendations on directions for its development in future. The Committee on Reforms in the Insurance Sector was appointed under the Chairmanship of Shri R. N. Malhotra, former Governor of the Reserve Bank of India. The Committee has recently submitted its report, which underlines the need for progressive deregulation of the insurance sector to create a more competitive and financially strong insurance industry functioning under an independent regulatory authority. The report is now under active consideration of the Government. It is my intention to evolve a broad national consensus about the future direction and content of reform in this important sector.

26. Efficient and abundant infrastructure services are a necessary precondition for the success of our economic reforms and especially for international competitiveness. Our electric power sector is faced with severe problems, including problems of financial viability of the State Electricity Boards which must

be solved if the supply of reliable power is to keep pace with ever-increasing demand. The sector requires major changes in the working of State Electricity Boards, rationalisation of tariffs and restructuring of responsibilities for generation, transmission and distribution. A Committee of the National Development Council is looking into a comprehensive reform of our power system and it will be necessary to face up to a number of hard decisions in this sector.

27. Significant steps have been taken in the oil and gas sector to promote investment including private investment in exploration, development, refining and marketing. We propose to deepen and intensify these initiatives. To promote modernisation and investment in the coal industry, Government is reviewing the policy framework for investment, pricing and distribution. New initiatives are under consideration in the Telecommunications Sector.

28. I shall now briefly go over the Revised Estimates for 1993-94.

29. Budget estimates for 1993-94 had placed the total expenditure at Rs. 131,323 crore. This is now expected to go up to Rs. 143,872 crore, that is, an increase of Rs. 12,549 crore.

30. Budget estimates for the current year provided Rs. 41,251 crore as budget support for Plan Expenditure. This is now being increased by Rs. 4,775 crore to Rs. 46,026 crore. Of this increase Rs. 3,493 crore are for assistance to States for financing their plans. A large part of this increase relates to externally-aided projects. I have also provided Rs. 856 crore as advance plan assistance to special category States to cover their opening deficits and Rs. 339 crore as additional special plan loan to Punjab to help that State in the process of recovery.

31. Under the Central Plan, a provision of Rs. 600 crore has been made for the new Employment Assurance Scheme announced by the Prime Minister on 15th August, 1993. I have also augmented the current year's provision for the National Renewal Fund by Rs. 320 crore, taking the total to Rs. 1,020 crore. This increase will fund implementation of Voluntary Retirement Schemes in Public Sector Undertakings and also finance training and counselling.

32. Non-plan expenditure in the current year will require an additional provision of Rs. 7,774 crore. An additional Rs. 2,200 crore has to be provided for food subsidy and Rs. 900 crore for fertilizer subsidy. I am including a provision of Rs. 632 crore towards assistance to States for providing concession to farmers on decontrolled fertilizers. It has also become necessary to provide an additional Rs. 2,320 crore for Defence expenditure. Honourable Members will appreciate that there can be no question of compromise on the external and internal security of our country. I am providing an additional Rs. 303 crore more for Police. Other increases include Rs. 219 crore for pensions and Rs. 500 crore for loans to States as their share of small savings collections, following improved collections.

33. Gross tax revenue, which was estimated in the Budget at Rs. 84,867 crore, is now expected to yield Rs. 8,117 crore less. Of this, about Rs. 822 crore is due to tax receipts of the National Capital Territory of Delhi flowing into its own Consolidated Fund from 1st of December, 1993. There is also a consequential reduction in expenditure on this account. The rest of the shortfall is mainly under Customs and Union Excise Duties. Customs revenue is Rs. 5,227 crore lower than expected mainly because imports have not increased as originally estimated. There is a shortfall of Rs. 2,001 crore in excise duty mainly due to the setback in production in certain high revenue yielding sectors of the economy. Due to the delay in finalisation of the procedure for disinvestment of equity holding in Public Sector Enterprises, the related receipts this year are estimated at Rs. 2,500 crore compared to the Budget estimate of Rs. 3,500 crore.

34. The shortfall in receipts has necessitated a larger resort to borrowings. However, I have made serious efforts to ensure that the increased borrowing does not lead to excessive growth of high powered money. Instead, we have seen to it that the Government has borrowed on the basis of market-related instruments such as the 364 days Treasury Bills which were started in 1992-93. We have also introduced certain other new instruments such as zero coupon rate bonds and 3 year loans for conversion of maturing 364 days Treasury Bills.

35. External loans net of repayments are placed at Rs. 3,837 crore compared to the Budget estimate of Rs. 5,454 crore.

36. Taking into account other variations in receipts and expenditure, the current year is expected to end with a budget deficit of Rs. 9,060 crore. The fiscal deficit, which was estimated at Rs. 36,959 crore in the original Budget, is now expected to go up to Rs. 58,551 crore. The fiscal deficit as a percentage of GDP will, therefore, be 7.3 per cent, which is much higher than projected at the budget stage. I am far from happy with this development. But, as I have stated earlier, there were special circumstances in 1992-94 which warranted somewhat higher deficit. In a situation characterised by idle industrial capacity. I was concerned that an attempt to bring about a sharp reduction in the fiscal deficit might well have been counter-productive. However, we cannot afford to repeat large fiscal deficits. We must return to the path of fiscal rectitude.

37. I now turn to the Budget estimates for 1994-95.

38. In order to maintain the tempo of development activities, the budgetary support for the Central Plan 1994-95 has been increased to Rs. 27,278 crore from Rs. 23,241 crore in Budget estimates 1993-94, an increase of about 17.4 per cent. The total outlay of the Central Plan of Rs. 70,141 crore for 1994-95 will be financed by budgetary support to the extent of 39 per cent as against 36 per cent in Budget estimates 1993-94. The balance of the Central Plan outlay will be financed by the internal and extra-budgetary resources of the Central Public Sector Enterprises.

39. I am providing Rs. 19,304 crore as Plan assistance to States and Union Territories in 1994-95 compared to Rs. 18,010 crore in Budget estimates 1993-94. The total budgetary support from the Central Government's budget to the Central and the State Plans will be increased by 13 per cent from Rs. 41,251 crore in Budget estimates 1993-94 to Rs. 46,582 crore in 1994-95.

40. The increased budgetary support to the Central Plan is being directed to support higher outlays in important social sectors such as Rural Development, Education, Health and Family Welfare and Women and Child Development, and Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. In response to the vital need for greater employment generation and capital formation in rural areas, and in order to focus more sharply on alleviation of rural poverty, the outlay for the Department of Rural Development has been increased from Rs. 5,010 crore in Budget estimates 1993-94 to Rs. 7,010 crore in 1994-95, representing a massive increase of 40 per cent over the previous year. Honourable Members will recall that the allocation for Rural Development was Rs. 3,100 crore in Budget estimates 1992-93. In two years, we have more than doubled this provision. For the new Employment Assurance Scheme announced by the Prime Minister on 15th August, 1993, which is being implemented in 1752 identified blocks, an outlay of Rs. 1,200 crore has been provided as compared to the 1993-94 outlay of Rs. 600 crore. Similarly, the allocations for the Jawahar Rozgar Yojana have also been enhanced from Rs. 3,306 crore in Budget estimates 1993-94 to Rs. 3,855 crore in 1994-95. It is estimated that 1150 million man-days of employment are likely to be generated in 1994-95. I have also increased the allocation for the Accelerated Rural Water Supply Programme, including the Rajiv Gandhi National Drinking Water Scheme, by Rs. 150 crore in 1994-95.

41. The Prime Minister's Rozgar Yojana was launched on October 2, 1993, to provide self-employment opportunities to one million educated unemployed youth in the country by setting up 7 lakh micro enterprises through industry, service and business ventures. The Scheme intends to cover urban areas during 1993-94 and whole of the country from 1994-95 onwards. A provision of Rs. 145 crore has been made for 1994-95.

42. The outlay for Agriculture will be Rs. 2,005 crore in 1994-95. A major thrust is being given to horticulture development, with a 42 per cent increase in allocation from Rs. 130 crore in Budget estimates 1993-94 to Rs. 184 crore in 1994-95. A major scheme for promoting use of plastics in drip irrigation is under implementation for which an enhanced outlay of Rs. 45 crore has been kept during 1994-95.

43. In the Eighth Plan, we have given high priority to the development of human resources. The bulk of outlay for this sector is in the plans of the States. The outlay for education in the Central plan is being increased by 17.6 per cent, to Rs. 1,541 crore in 1994-95. Special efforts are being made for strengthening of elementary education, for which the outlay

has been increased from Rs. 442 crore in Budget estimates 1993-94 to Rs. 523 crore in 1994-95. The allocation for the University Grants Commission has been increased from Rs. 159 crore in the Budget estimates for 1993-94 to Rs. 209 crore in 1994-95. Special allocations have been made to upgrade the quality of libraries and laboratories in the system of higher education. Provision has also been made for the establishment of an Indian Institute of Technology and for two Central Universities in Assam.

44. The outlay for Health has been increased by nearly 20 per cent from Rs. 483 crore in Budget estimates 1993-94 to Rs. 578 crore in 1994-95. A revamped National Programme for the Control of Blindness, will be implemented from the next year. The allocation for the Leprosy Eradication Programme has been increased from Rs. 35 crore in Budget estimates 1993-94 to Rs. 94 crore in 1994-95. Control and prevention of AIDS is of paramount importance; an increased provision of Rs. 83 crore has been made for 1994-95.

45. The outlay for the Department of Family Welfare has also been increased from Rs. 1,270 crore in Budget estimates 1993-94 to Rs. 1,430 crore in 1994-95.

46. The provision for the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, inclusive of support to States for specified schemes, has been increased in 1994-95 to Rs. 982 crore. The share capital contribution by the Central Government to the National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation and the National Backward Classes Finance and Development Corporation is being increased from Rs. 53 crore in Budget estimates 1993-94 to Rs. 76 crore in 1994-95.

47. Recognising the critical role of infrastructure, Plan outlays in Power, Petroleum and Natural Gas, Telecommunication, Railways and Transport, have all been increased. The Plan outlay for power sector has been raised from Rs. 7,461 crore in Budget estimates 1993-94 to Rs. 8,464 crore in 1994-95; and within this total, the budget support for this sector has been increased by over 27 per cent from Rs. 2,445 crore in Budget estimates 1993-94 to Rs. 3,117 crore in 1994-95. The Plan outlay for the Telecommunication services has been increased from Rs. 6,321 crore in Budget estimates 1993-94 to Rs. 7,246 crore in 1994-95. The outlay for Roads has been stepped up from Rs. 593 crore in Budget estimates 1993-94 to Rs. 665 crore in 1994-95. We have also increased the budget support to the Railways by 20 per cent from Rs. 960 crore in Budget estimates 1993-94 to Rs. 1,150 crore in 1994-95. To sustain long-term development, cost recovery for infrastructure services has to become much more effective. Investments in infrastructure sectors must increasingly be financed through internal and extra-budgetary resources of Public Sector Undertakings.

48. The role of science and technology is critical for modernising our economy and making it globally competitive. The outlay for the Department of Science & Technology has been raised by 19 per cent from Rs. 189 crore in Budget estimates 1993-94 to Rs. 225 crore in 1994-95.

49. Total non-plan expenditure next year is placed at Rs. 1,05,117 crore compared to Rs. 97,846 crore in the Revised estimates of current year. I have to draw the attention of the Honourable Members to a major factor which has been contributing to the sizeable increase in non-plan expenditure year after year, and this is the interest burden. The provision for interest payments next year is placed at Rs. 46,000 crore. This is an increase of Rs. 8,000 crore over the current year's Budget estimates whereas the increase in total non-plan expenditure is Rs. 15,045 crore. Honourable Members will appreciate that the major part of the interest burden is a legacy from the past and it continues to grow because of the continued high level of Government borrowing. Interest payments can be reduced only if we can implement a programme of phased reduction in the Government's total borrowing requirements or fiscal deficit. This can become a reality only if our tax system becomes more buoyant, our public enterprises generate more internal resources and we reduce expenditure on subsidies. A bold programme for disinvestment of government equity in public enterprises and earmarking a part of the sale proceeds purely for debt reduction would also be of great help.

50. Defence is another important element in non-plan expenditure. We cannot take chances with our national security. I am, therefore, providing Rs. 23,000 crore for Defence as against Rs. 19,180 crore in the Budget estimates for 1993-94 which was itself raised to Rs. 21,500 crore in the Revised estimates. I am providing Rs. 4,000 crore each for food subsidy and fertilizers subsidy. I am also providing Rs. 341 crore being the balance amount payable by Government under the scheme of Debt Relief to Farmers. Furthermore, I am providing for a net expenditure of Rs. 365 crore on account of Government's assumption of exchange loss liability on Foreign Currency Non-Resident Accounts Scheme, which was previously borne by the Reserve Bank of India.

51. The provision made in next year's Budget for non-plan expenditure other than the provisions for interest payments and defence is actually Rs. 2,729 crore less than in the Revised estimates for the current year.

52. Coming to receipts, gross tax revenue at existing levels of taxation is placed at Rs. 87,136 crore. States' share of taxes next year is estimated at Rs. 24,394 crore compared to Rs. 22,244 crore in the Revised estimates of the current year. External loans net of repayments are placed at Rs. 4,279 crore compared to Rs. 3,837 crore in the current year's Revised estimates.

53. Taking into account maturing liabilities, the net Small Savings collections next year are placed at the same level as in the current year, that is, Rs. 6,000 crore. I am taking a credit of Rs. 4,000 crore next year as receipts from disinvestment as a continuation of the policy of mobilising non-inflationary resources from the sale of public sector equity. Total receipts are estimated at Rs. 1,45,699 crore and total expenditure at Rs. 1,51,699 crore leaving a gap of Rs. 6,000 crore.

PART B

54. I now turn to the tax proposals for 1994-95. This year I shall begin with the proposals relating to indirect taxes.

55. Over the years, our indirect tax structure has grown into a complex maze of high and multiple rates, with numerous exemptions, and different rates being applicable for the same product of different uses and users. This has resulted in unnecessary complexity leading to administrative abuse, mounting litigation and uncertain economic impact. All this has effectively eroded the tax base and buoyancy of the system and created serious economic distortions. My proposals, in both customs and central excise, aim at simplifying the structure and continuing the process of moving to moderate rates of taxation.

56. Customs duties though lowered in the past three budgets need to be brought down further to make key imported raw materials and capital goods available to Indian industry at reasonable costs and also to reduce unduly high levels of protection to industry. At the same time, the scale of duty reduction has to be calibrated to ensure that it does not place unreasonable pressure on domestic producers of similar products. In this framework, the key features of my customs tariff reform proposals are :—

- * Further reduction in the peak rate of customs duty;
- * Substantial reduction in duties on key raw materials, such as steel and chemicals;
- * Reduction in customs duties on capital goods to boost investment combined with other incentives which will help the domestic capital goods industry;
- * Reduction or removal of anomalies caused by import duties on raw materials and components being higher than on finished products;
- * A systematic effort to unify rates on similar products to serve both economic rationality and to reduce the scope for classification disputes;
- * A major pruning of notifications including end use exemptions to about half their present number, thus reducing discretionary power and possibilities for disputes.

57. I propose to reduce the peak rate of customs duty from 85 per cent to 65 per cent. Items like baggage and liquor will however continue to attract higher duty as at present.

58. Availability of capital goods at a reasonable cost is necessary to enhance our competitiveness and promote investment. It is also necessary to ensure that our domestic capital goods industry, which has tremendous potential, is not at a comparative disadvantage due to anomalies in the tax structure. To

further both these objectives, I propose the following package of measures :

- (a) I propose to reduce basic customs duty on project imports and general capital goods from 35 per cent to 25 per cent. The facility of project imports is being extended to include port development. All this will help to reduce cost of investment and modernisation in Indian industry. Import duty on parts, whether imported as parts of original equipment, or as spares is also being reduced to 25 per cent from the present rates varying from 25 per cent to 85 per cent. Import duty on fertiliser projects and power projects will continue at nil rate and 20 per cent respectively without any countervailing duty.
- (b) Domestic suppliers of capital goods have consistently argued that if domestic capital goods are to compete with imports, there should be a countervailing duty on imports of capital goods equivalent to the excise duty on domestic capital goods. I propose to accept this demand.
- (c) I am simultaneously extending the benefit of Modvat to capital goods so that full credit of excise duty paid on domestic capital goods or countervailing duty paid on imported capital goods will be available at one time. This has been a long standing demand of all sectors of Indian industry.
- (d) At present, machine tools attract duty at varying rates of 40 per cent, 60 per cent and 80 per cent. I propose to simplify the structure by charging duty at 35 per cent or 45 per cent only.
- (e) With the reduction of duty on finished capital goods it is necessary to reduce the customs duty on steel, which is a key input. I propose to reduce the customs duty on steel from a range of 75 per cent to 85 per cent at present to 50 per cent. Import duties on primary forms of major non-ferrous metals copper, zinc and lead are also being unified at 50 per cent. These proposals will give a strong boost to investment in the economy and will help the domestic capital goods industry, in particular.

59. To help domestic metal producers, the import duties on all ores and concentrates are being reduced and unified at 10 per cent. To reduce the cost of inputs for the secondary steel sector, I propose to reduce the import duty on melting scrap from 12.5 per cent to 10 per cent and on iron ore pellets from 15 per cent to 10 per cent.

60. In order to give a thrust to the export efforts of our leather industry, which is a major export earner, and is also employment intensive, I propose to reduce import duty on a large number of items of machinery and raw materials used in this industry from rates varying from 25 per cent to 50 per cent at present to a uniform level of 20 per cent without the addition of countervailing duty.

61. Electronics and telecommunication are vital for rapid economic development and can greatly contribute to generation of both additional employment and exports. I propose to rationalise the tariff structure for these sectors as follows :

- (a) The import duty on computer parts is being reduced from 80 per cent to 50 per cent. The duty on specified components is being reduced from 50 per cent to 40 per cent and on specified piece parts from 35 per cent to 30 per cent. The import duty on application software is being reduced from 85 per cent to 20 per cent.
- (b) In order to encourage the telecommunication sector, I propose to reduce import duty on non-electronic parts for manufacture of such equipment from 50 per cent to 40 per cent and on optical fibre from 85 per cent to 40 per cent to encourage manufacture of optical fibre cables in the country.

62. The domestic watch industry has a significant growth potential. To enable this industry to become internationally competitive, I propose to reduce the import duty on certain items of machinery for the industry from 50 per cent at present to 25 per cent. I also propose to reduce the duty on certain components and raw materials for the watch industry from 70 per cent and 50 per cent at present to 25 per cent and 20 per cent respectively.

63. The present import duty structure for medical equipment is complex and involves in some cases time consuming administrative procedure. The domestic industry is also not able to compete with imported equipment because it is now available duty-free to hospitals on production of certificates by designated authorities. In order to remove the above hindrances, I propose to abolish the system of certification for charitable hospitals and freely permit import of specified medical equipment at 15 per cent without any countervailing duty. The list of such equipment is being separately notified and can be expanded on merits. Import at zero rate for government hospitals and for all specified life saving and sight saving equipment is, however, being continued. Import duty on other medical equipment which is at present 85 per cent is being reduced to 40 per cent. Components for their manufacture will be allowed to be imported at 15 per cent customs duty. This differential will help manufacture of medical equipment by indigenous industry.

64. The import duty structure for coal and petroleum is being simplified. Crude petroleum and coal will attract import duty of 35 per cent as against Rs. 1500 per metric tonne and 85 per cent respectively. Duty on coke is being reduced from 85 per cent to 25 per cent. LPG and other petroleum gases will attract import duty at 15 per cent. Naptha and kerosene will continue to be exempted from basic customs duty. Other petroleum products will attract an import duty of 30 per cent. These changes do not affect the administered prices of petroleum products to consumers.

65. The present import duty structure for chemicals provides for a lower rate of duty of 15 per cent for the basic feed stocks and peak rate of 85 per cent for the finished chemicals. The overall dispersal of the rates is being reduced by the reduction of peak rate to 65 per cent. In addition, duties on DMT, PTA and MEG are being reduced from 70 per cent to 60 per cent and on intermediates like xylenes and toluene, the duty is being reduced from 40 per cent to 30 per cent. The 15 per cent rate for basic feed stocks has been kept undisturbed.

66. In the pharmaceutical sector, import duty on a large number of raw materials which at present varies from 85 per cent to 50 per cent is being lowered to two rates of 50 per cent or 25 per cent. In a few cases, there has been some upward adjustment of import duty having regard to the need to protect the interest of domestic manufacturers of drug intermediates.

67. While I have no doubt that the phased reduction of customs tariffs is essential for the longer term interest of our industry, I am also fully aware of the concern of some industries about the dumping of certain imported goods at artificially low prices. I assure the House that our anti dumping provisions will be reviewed and further strengthened, if necessary.

68. I now turn to my proposals for central excise.

69. This Budget proposes a major reform of the excise tax structure as part of our programme of modernising our tax system. The principal features of this restructuring are :

- * Extension of Modvat to capital goods and petroleum products;
- * Shift in the bulk of excise taxation from specific to ad valorem rates which will assure much greater built-in buoyancy of revenues.
- * Reduction in the total number of ad valorem tax rates to about half the existing number which will be a major step towards simplicity and transparency;
- * Continuing the process of lowering rates when they are unduly high;
- * Application of uniform rates or similar commodities to the extent possible. This will reduce classification problems, scope for misuse and widespread litigation;
- * Removal of complicated price list procedure;
- * Reduction of the number of special exemption notifications by about half.

70. These steps will promote growth of manufacturing output and employment, will make tax administration easier, less discretionary and also reduce the scope for misclassification, disputes and evasion. They will increase revenue elasticity and pave the way for an eventual adoption of a Value Added Tax.

71. Inevitably, a major restructuring involves changes in many rates for several products as products have to be reclassified into fewer rate categories. Furthermore, duty rates have been adjusted in some cases to compensate for loss of revenue because of the extension of Modvat. However, I have ensured that items of mass consumption are not burdened by higher taxes. For example, full exemption continues for many goods such as handloom products, unbranded drugs, domestic electric bulbs, bicycles, baby food, cooking oil, spices, jams, jellies, sauces, tea and coffee. And care has been taken not to raise the rates on, for example, sugar, matches and vanaspati. There should be no adverse effect on prices of essential items of consumption of the common man.

72. I will now highlight a few major areas of special interest.

73. Sir, the House may recall that the Modvat scheme was introduced in 1986. Its subsequent extension has greatly helped to reduce the cascading effect on input taxes. But the coverage remains incomplete. Petroleum products, textiles, matches, tobacco products and capital goods had been left out of the scheme. There is a persistent demand from industry to make the scheme more comprehensive. I now propose to extend the Modvat scheme to two important sectors namely, capital goods and petroleum products.

74. I propose to rationalise the structure for petroleum products. At present, the excise duty rates are specific. There are numerous exemptions depending on the end use. I propose to replace the existing specific rates by a uniform advalorem rate of 10 per cent on all petroleum products with the exception of motor spirit which will attract duty of 20 per cent. End use exemptions will be virtually eliminated. Existing concessions for the fertilizer industry are, however, being continued. These changes have no impact on the administered prices of these items.

75. The current duty structure for cotton and man made fabrics is a combination of ad-valorem and specific rates. I propose to switch over to ad-valorem rates of 5 per cent, 10 per cent and 20 per cent only instead of the numerous specific and ad-valorem rates currently prevailing.

76. The present excise duty structure on fibres and yarns is complicated and different specific rates are prescribed for different varieties of yarn and fibres. This has required frequent testing of samples to determine the correct duty liability. In order to obviate all problems of classification and to make the excise duty neutral as between various fibres and yarns, I propose to impose a uniform excise duty of 20 per cent on all fibres and blended or spun yarns. On cotton yarn, excise duty is, however, proposed at 5 per cent only instead of the present complex and varying specific rates depending on the count of the count of the yarn. As regards filament yarns, revenue considerations preclude moving to a uniform excise duty. I have thus proposed an ad-valorem duty rate of 60 per cent for polyester filament yarn, 30 per cent for nylon and polypropylene yarn and 15 per

cent for viscose filament yarn. For industrial yarns, lower rates of 30 per cent, 20 per cent and 10 per cent have been prescribed. The scheme of Modvat is being extended to yarns made from fibres. With this Modvat will cover all yarns. These changes are largely a simplification and rationalisation of the structure. Combined with the reduction in customs duties, they should help to moderate prices in this sector.

77. I propose to fix a uniform duty of 15 per cent on all metals, except aluminium for which the duty will be 20 per cent as against 25 per cent now. However, a lower duty of 10 per cent will be available to pig iron and certain other products of iron.

78. The excise duty structure on drugs differentiates between Schedule I, Schedule II and other drugs. Schedule I drugs which are for the National Health Programme and are under price control are fully exempted from excise duty. This will continue. Single formulations of Schedule II drugs attract excise duty at 10 per cent while other branded drugs pay excise duty at 15 per cent. I propose to unify these rates at 15 per cent. I propose to charge a moderate 10 per cent excise duty on branded ayurvedic and homoeopathic medicines and medicines of other alternative systems. At present, bulk drugs producers cannot get full benefit of Modvat credit because the excise duty on bulk drugs is 5 per cent which is too low. This is being raised to 10 per cent to enable them to get full credit. Unbranded drugs however, will continue to be exempted from excise duty.

79. In order to simplify the duty structure for various chemicals and chemical based products like dyes, paints, tanning preparations, etc., I am proposing a uniform duty of 20 per cent on such products instead of present rates varying from 5 per cent to 25 per cent. A uniform duty of 30 per cent is being proposed for major bulk plastics, synthetic paints and detergents, which currently attract 35 per cent.

80. The paper duty structure is complicated due to ad-valorem rates of nil, 10 per cent, 15 per cent, 25 per cent, 30 per cent, specific rates and specific cum ad-valorem rates. This is now being simplified by making the general rate of duty on paper at 20 per cent, keeping nil rate for news print, stationery articles etc., 30 per cent for paper based laminates and floor coverings and 10 per cent or 15 per cent for paper made from unconventional raw materials. I am enlarging the scope of the exemption currently available to paper mills using unconventional raw materials. This exemption limits the benefit by clubbing the clearances of paper from more than one factory of a manufacturer. I am now allowing this concession to be availed of by each factory separately.

81. The duty rate of 70 per cent applicable to cosmetics and similar personal care products are too high for items which are now increasingly forming part of the consumption basket of ordinary people. The rate is, therefore, being reduced to 50 per cent.

82. I am also proposing certain changes in the general small scale industry exemption scheme. At present only registered units are eligible for concessions upto a clearance value of Rs. 75 lakhs. Non-

registered units can get exemption only up to Rs. 30 lakhs. I propose to do away with this distinction so that small scale units can get the exemption meant for them irrespective of whether they are registered or not. This will satisfy one of the major demands of small scale industry. The scope of the small scale exemption scheme is also being expanded to cover a number of additional items including certain non-steel and copper products.

83. Under the present scheme, a small unit manufacturing goods under the brand name of another unit is entitled to duty concession only if the brand name does not belong to a large unit. There have been reports of bigger units avoiding payment of duty by getting their brand names registered in the name of smaller units. This does not allow a small manufacturer to promote his own brand. With the advent of international brand names in the country, it is necessary to check the misuse of the scheme in the interest of domestic industry. I therefore, propose that the benefit of duty concession would not be available to clearances of goods bearing the brand name of another manufacturer.

84. One of the persistent demands of the small scale industries has been to allow them to pay duty even though they are otherwise entitled to exemption as this will enable their customers to claim the benefit of Modvat credit. There is considerable merit in this request, and I propose to give the option to those who will like to exercise it.

85. It may be recalled that in the last budget, in order to give encouragement to the ship breaking industry, basic customs duty on ships for breaking up was reduced to 5 per cent. Countervailing duty was payable in addition. Ferrous metals obtained from breaking up of ships were consequently exempted from excise duty. There have been some disputes regarding liability of countervailing duty on ships for breaking up. In order to obviate the disputes, I propose to exempt ships for breaking up from countervailing duty and correspondingly adjust the basic customs duty to 15 per cent. For the ship breaking industry, all goods obtained from such breaking up are also proposed to be exempted from excise duty so that ship breaking activity is completely outside the excise control.

86. As I am continuing the specific rates of duties on cigarettes, and these have remained unchanged for two years despite an increase in price, I propose to increase the duties on cigarettes by about 12 per cent. However, in the non-filter segment, the excise duty for upto 60 mm category is being reduced from Rs. 120 per thousand to Rs. 60 per thousand, for increased utilisation of tobacco in this industry, which would in turn help the tobacco growers.

87. Over the years, while attempts have been made to widen the base for domestic indirect taxes, the services sector has not been subjected to taxation. Yet this sector accounts for about 40 per cent of our GDP and is showing strong growth. There is no sound reason for exempting services from taxation, when goods are taxed and many countries treat goods and services alike for tax purposes. The Tax

purposes. The Tax Reforms Committee has also recommended imposition of tax on services as a measure for broadening the base of indirect taxes. I, therefore, propose to make a modest effort in this direction by imposing a tax on services of telephones, non-life insurance and stock brokers. The tax will be changed at 5 per cent on the amount of telephone bills, the net premium charged by the insurance companies, and the brokerage or commission charged by the stock brokers in relation to their services. These proposals will come into force from a date to be notified later on.

88. The existing system of determination of value of goods for charging excise duty is cumbersome and time-consuming. It involves filing of price lists in advance by the assessee and their approval by the excise officer. The process has to be followed whenever there is a change in the price. As a measure of procedural simplification, I have decided to dispense with the requirement of price lists. The assessee will now be allowed to pay excise duty on the basis of the value arrived at from the invoice. I am sure that this facility will be widely welcome by the industry. This will also help lay the ground for eventual adoption of a value added tax which relies on invoice value.

89. The details of the revenue implications of the measures announced are given in the Explanatory Memorandum to the Finance Bill.

90. I have also proposed certain other amendments in the Finance Bill seeking to effect changes in the Customs Act, and Excise and Customs Tariffs. The amendments are merely enabling provisions and do not have significant revenue implications. Besides, there are proposals for amendment of some of the existing notifications. In order to save the time of the House, I do not propose to recount them.

91. Copies of notifications giving effect to the above changes in customs and excise duties will be laid on the Table of the House in due course.

92. I now turn to my direct tax proposals for 1994-95.

93. I propose to carry forward the basic philosophy which has guided our tax reforms of moving to a simpler system with moderate rates of tax and a much greater reliance on broadening the base, with better tax administration.

94. I have received numerous representations from workers, trade unions, and other bodies representing middle class citizens for raising the exemption limit for income tax which is now Rs. 30,000. I am persuaded that there is merit in the demand and I propose to raise the exemption limit to Rs. 35,000. With this, a salary or wage earner with a gross income of Rs. 50,000 will pay no income-tax. A working woman with a salary of Rs. 52,000 will also pay no tax.

95. I also propose to adjust the tax slabs which have not been changed for two years. At present, the first bracket is from Rs. 30,000 to Rs. 50,000 with a tax rate of 20 per cent. Henceforth the first slab will be Rs. 35,000 to Rs. 60,000, with the same rate

of 20 per cent tax. The second slab at present is from Rs. 50,000 to Rs. 1,00,000 with a tax rate of 30 per cent. Hereafter, the second slab will be Rs. 60,000 to Rs. 1,20,000 with the same rate of 30 per cent. tax. The maximum tax rate of 40 per cent, which at present applies to incomes above Rs. 1,00,000 will henceforth be applicable to incomes above Rs. 1,20,000.

96. I had stated last year that I was forced to retain the surcharge of 12 per cent on non-corporate incomes for one more year. I am happy to announce that I now propose to withdraw the surcharge completely.

97. Last year, I had indicated that while major reforms of the corporate tax structure are desirable they would have to be deferred by one year. I now propose to implement these reforms which will help both our private and public sector companies to save more, invest more and become more competitive.

98. At present, widely held companies are taxed at 45 per cent, while other domestic companies attract 50 per cent. tax. I propose to do away with the distinction which now exists between the tax rates for widely held and closely held domestic companies and lower both rates to a single rate of 40 per cent.

99. All domestic companies having income exceeding Rs. 75,000 are liable to pay surcharge at the rate of 15 per cent. Much as I would like to eliminate this surcharge, revenue constraints compel me to continue this levy for the present. The tax on companies incorporated abroad, but earning income in India, is 65 per cent at present. In line with the general reduction in corporate tax rates, this rate is being reduced to 55 per cent.

100. One of the consequences of our economic policies is the need to assist Indian companies to restructure themselves to improve their competitive position in the market. This may call for divestment of part of the business assets or realisation of potential value from dormant assets, both of which will entail long-term capital gains tax. This acts as a deterrent to re-structuring. The present rate of such long-term capital gains tax on domestic companies is 40 per cent, whereas long-term capital gains of individuals are taxed at only 20 per cent. I, therefore, propose to lower the rate of capital gains tax on domestic companies to 30 per cent.

101. I also propose that, just like shares, even units of Unit Trust of India and other approved Mutual Funds, if held for more than 12 months, will be treated as long-term capital assets, with consequential benefits, the required holding period for such units at present is 36 months. This will bring some welcome relief to investors in units who generally belong to lower, middle or middle classes.

102. The rates of taxation of investment income (i.e. dividend and interest income) of non-residents vary with the tax status of the recipient. I propose to rationalise the scheme of such taxation by having a uniform rate of 20 per cent on such income in the hands of all non-resident companies and non-resident individuals (be they Indians or foreign nationals).

103. Representations have been received from Non-Resident Indians that they should not lose their Non-Resident status even if they visit India and stay for more than 149 days. I propose to raise this period of stay to 181 days.

104. Two years ago I introduced a special tax rebate for senior citizens (i.e., those aged 65 and above) at 10 per cent of the tax due if their income was below Rs. 50,000. Last year I increased the tax rebate to 20 per cent and also increased the income limit to Rs. 75,000. I now propose to raise the tax rebate admissible to them from 20 per cent of the tax due to 40 per cent and make the benefit available to senior citizens having income upto Rs. 1 lakh.

105. In 1992, we had decided to club the income arising to a minor child with that of the parent. This causes undue hardship in cases involving handicapped children and their parents. In order that the post-tax income of a child who is physically handicapped is not reduced, I propose to exempt the incomes of such handicapped children from the provisions of clubbing, both under the Income-tax and Wealth-tax Acts.

106. For enabling self-employed people to contribute to a pension fund to provide for security in their old age, the Unit Trust of India is going to set up a fund. I propose to include contributions to such a pension fund among the amount which qualify for tax rebate under Section 88 of the Income-tax Act.

107. Investment in the development of human resources is an essential pre-requisite for growth and progress. Several students take loans for their studies. As a means of helping students from poorer families, who take loans from financial institutions, I propose to allow a deduction from income of Rs. 25,000 per year on account of repayments of principal and payment of interest up to a cumulative total of Rs. 2 lakhs. This tax concession will be available to students who undertake graduate or post-graduate studies in Engineering, Medicine or Management, or post-graduate studies in pure sciences, applied sciences, Mathematics or Statistics.

108. Encouragement of science and technology is essential for promotion of growth. At present, when an assessee makes a contribution to a National Laboratory under the aegis of Indian Council of Agricultural Research, Indian Council of Medical Research or Council of Scientific and Industrial Research, he or she gets a weighted deduction of 125 per cent of the contribution. I propose to extend this benefit to all Universities, deemed Universities, Indian Institutes of Technology and scientific laboratories under the aegis of the Defence Research and Development Organization, the Department of Electronics, the Department of Bio-technology and the Department of Atomic Energy.

109. Several Universities and Co-operative Societies have made representations that the tax exemption under section 10(10C) for approved Voluntary Retirement Schemes should be extended to their employees. I propose to accept their representations.

110. A statement has already been made in the last session of Parliament, signifying Government's intention to exempt the income of Government Corporations established for the welfare of the backward classes. I propose to make legislative amendments for carrying out this commitment.

111. The system of community of property (COMMUNIAO DOSBENS) is peculiar to the people living in Goa, Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli. Recently, certain judicial decisions have been handed down according to which business income of a Goanese family becomes taxable entirely in the hands of a single entity. The decisions affect the time-honoured method of dividing such income equally and assessing such income separately in the hands of the husband and wife. This I understand has given rise to unnecessary tension and anxiety amongst the Goan couples. To set at rest all controversies in this area, I propose to make suitable amendments in the Income-tax Act to ensure that, excepting for salaries, any other income arising to the citizens governed by the system of community of property in Goa will be divided equally and assessed separately in the hands of the husband and the wife.

112. We have, in the last few years, liberalised the taxation of perquisites in the form of medical expenditure in the case of employees. I propose extending the scope of the benefit by including re-imbursement of bills paid by employees to recognised private hospitals.

113. In order to give relief to those living in their own houses and as an incentive for house construction, I propose to raise the deduction on account of interest on borrowed capital for house construction from Rs. 5,000 to Rs. 10,000 for purposes of income tax.

114. We have been implementing a simple presumptive scheme of taxation for the assesses in the unorganised sector for the past two years. The scheme was to have ended with this year. I propose to continue with the scheme. My hope is that more people will avail of this very simple scheme and come forward readily to contribute their mite to the national tax effort without any fear or inhibition.

115. In addition, I am introducing a new estimated income scheme for contractors with a turnover of upto Rs. 40 lakhs and for truck-owners who own upto ten trucks. In the case of contractors, the net profit will be estimated at 8 per cent of the gross receipts. In the case of truck owners, the income will be estimated at Rs. 24,000 per truck per year for Light Commercial Vehicles and Medium Motor Vehicles, and Rs. 30,000 per truck per year for Heavy Transport Motor Vehicles. In both these cases, no further deduction on account of depreciation or interest or other expenses will be allowed. In both cases, the scheme is optional. This scheme is based on the recommendation of the Chelliah Committee on Tax Reforms. The scheme will be simple and free of irritants, and I expect an enthusiastic response.

116. Last year, I announced a five-year tax holiday to new industrial undertakings commencing production in States specified in the Eighth Schedule to the Income-tax Act. There have been repeated and widespread demands that the benefit should be extended to backward districts in other States. I had announced the setting up of a Study Group to go into this question. The Group's report has been received and is under consideration. As a stimulus to new investment in backward districts in other States of the country, I propose to extend this concession to such districts which are backward according to certain guidelines which will be prescribed.

117. Government has already announced its intention of growing the deduction in respect of profits of new industrial undertakings engaged in the manufacture of items listed in the Eleventh Schedule of the Income-tax Act to large-scale units also, provided such units are set up in the backward States enumerated in the Eighth Schedule. I propose to give legislative shape to this intention.

118. In order to continue to give encouragement to the export of computer software, I propose extending the exemption for such export profits for one more year.

119. We have an ambitious programme of attracting tourists to this country. It has been strongly urged that the present rate of tax on expenditure incurred in hotels discourages tourism. I therefore, propose to reduce the rate of expenditure tax from 20 per cent. to 10 per cent. I am doing so on the expectation that the State Governments too will follow suit and reduce their taxation on hotels in order to encourage tourism within the country and attract more foreign tourists to our land.

120. Pollution control is of vital importance to all of us. I, therefore, propose to include pollution control among the eligible projects for concession under section 35 AC of the Income-tax Act, so that a person who makes a contribution to such a project can claim 100 per cent of such contribution as a tax deduction.

121. The exemption limit for gift-tax is Rs. 30,000 and an additional exemption of Rs. 30,000 is available for gifts to dependant relatives on the occasion of marriage. Marriages are joyous occasions of family re-union, and honest tax-paying citizens have a right to be free from tax considerations as far as possible on such auspicious occasions. I, therefore, propose to raise the exemption for such gifts on the occasion of marriage of a dependant relative from Rs. 30,000 to Rs. 1,00,000.

122. As conventionally estimated, the proposed changes in custom duties will result in a revenue loss of Rs. 2,981 crores and a revenue gain of Rs. 699 crores. On the Excise side, the revenue gain is anticipated at Rs. 2,106 crores and relief will amount to Rs. 2,000 crores. The effect of changes in Direct taxes will result in a loss of Rs. 1,075 crores in the personal Income-tax collections and Rs. 1,355 crores in Corporation tax. The estimated loss on Expenditure-tax is Rs. 75 crores.

Taking into account an estimated gain of Rs. 600 crores on account of taxes on services, the total net loss on account of tax measures by conventional methods of calculation amounts to Rs. 4,081 crores. The loss to the States on account of reliefs in personal Income-tax is Rs. 625 crores and the gains on the Excise duty Rs. 148 crores. On the basis of these calculations, the Centre will suffer a net loss of Rs. 3604 crores.

123. Normally, a revenue loss of this magnitude at the time when the fiscal system is under pressure would require levy of additional taxes or an increase in existing rates. I have not followed this course of action for several reasons. The revenue loss calculations do not give any credit for simplification and rationalisation of the tax structure which will help revenue collections. Fiscal experts are near unanimous that there is considerable evasion of taxes in our system and that it is possible to reduce tax rates and yet mobilise additional revenue by improving tax administration and compliance. The simplification in the indirect tax structure that is now being introduced, will reduce the scope for discretion, disputes and litigation, all of which are a source of tax evasion. The shift to ad valorem excise duties will also add to buoyancy. I also propose to make a major effort at improving tax administration. Tax laws are going to be administered fairly and firmly. Computerisation, which has already begun in both Departments is expected to further improve tax administration. I also hope that tax payers who have long argued for moderation in the rates of taxes and held out assurances that this would improve compliance will now live up to their side of the bargain. They have, in the long run, the most to gain from the success of this experiment.

124. Economic life everywhere is characterised by great uncertainty. There is always the possibility that things may not work out the way I have assumed. Although one cannot be dogmatic in these matters, my considered view is that the risks involved in the course of action I have proposed, do not cross the limits of prudence. The consequence of postponing the tax reform, or of imposing additional taxes to offset the revenue loss as conventionally calculated, would wholly unproductive in a situation where our economy is characterised by sizeable unutilized industrial capacity, record food stocks and comfortable foreign exchange reserves. Any such course could give a setback to the economic recovery which our country needs, and which is now on the horizon.

125. For these reasons, I do not propose to assume any revenue loss as a result of the Budget proposals. The Budget deficit will therefore remain at Rs. 6,000 crores and the fiscal deficit at Rs. 54,915 crores. At this level, the fiscal deficit will be around 6 per cent. of GDP. This is higher than I would like to see, but as I have said, all tax reforms involve some risks.

126. This Budget is being presented at a critical time for the economy. There are moments in history which call for determined and decisive action. The consequences of inaction or ill-designed res-

ponses can be horrendous and are felt for decades to come. June, 1991 was such a moment. Thanks to the magnificent leadership provided by the Prime Minister Shri P. V. Narasimha Rao, we have been successful in reversing the adverse tide in our fortunes. However, the task of national reconstruction is by no means over. It is by its very nature a task which should occupy us for the rest of the decade. But we pursue this task today from a stronger position. The economy has been restored to health and shows all the potential for rapid growth in the years ahead. Our agricultural sector is strong and well placed to respond to the new policies. Our industrial sector, both, private and public, has begun the difficult process of restructuring to face increasingly competitive market conditions. The climate for investment—both domestic and foreign—has vastly improved. The tax structure now proposed goes a long way towards the kind of modern tax system and moderate tax rates and an emphasis on compliance, which is the hallmark of all successful countries. I am confident that it will provide a strong stimulus for new investments, economic revival and international competitiveness which is what the economy needs today. The medium term objectives set out in the report of the Tax Reform Committee are now clearly within our reach.

127. Mr. Speaker, Sir, this Budget is inspired by a firm conviction that India has all the material and human resources to be a front-ranking nation of the world. We are on the threshold of a new century, indeed a new millennium. There are tremendous opportunities, provided we have the wisdom and foresight to seize them. There are also immense dangers if we falter or appear indecisive. Sir, this then is a time for hard work, for recapturing the high noon of idealism which inspired our freedom struggle, for a firm determination to hold aloft, undimmed and untarnished, the bright torch of India which, as Jawaharlal Nehru was fond of saying, embodies her great and eternal spirit so that its light reaches every home and rekindles hope, faith and courage, and pride in being an Indian. Let us strive tirelessly, as the great poet Rabindranath Tagore said in his prayer, to build an India where "the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit". May we worthy of this noble task and of this ancient and sacred land of India.

128. Sir, I commend the Budget to this august House.

N. P. BAGCHEE, Addl. Secy. (Budget)